RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, ये वही लोग है जो आपको छलांग लगाना सिखाऐंगे।

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

वर्ष-07, अंक - 52 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 18 सितम्बर 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में एसआरआई करवाने की तैयारी

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई व वोट चोरी के आरोपो के बीच बिहार की तर्ज पर पूरे देश में मतदाता सूचियो का विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात (एस आर आई) करवाने को लेकर कमर कस ली है। आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि, वे 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया के लिए तैयार रहे। जिसके बाद यह माना जा रहा है कि, चुनाव आयोग अक्टूबर के अंत या नवंबर के प्रारंभ में देश भर में मतदाता सूचियां का सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर सकता है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियां का सत्यापन का कार्य वर्ष 2002 व 2004 के बीच हुआ था। ऐसे में इन सूचियो का सत्यापन आवश्यक भी था क्योंकि 20 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है और बड़ी संख्या में लोग अपने मूल स्थान से अन्यत्र चले जाते हैं जिससे उनका नाम दो जगह भी मतदाता सूची में शामिल हो जाता है। यही नहीं अनेक स्थानों पर मृत व्यक्तियों के नाम भी मतदाता सूची में बने रहते हैं, बिहार में हुई एस आर आई में यह तथ्य भी सामने आया है। यही नहीं बिहार की मतदाता सूची के सत्यापन में अवांछित लोग बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाल आदि घुसपैठियों के नाम भी सामने आए थे। जिसके बाद यह आशंका जाहिर की जा रही है कि, इसी प्रकार की स्थिति पूरे देश की मतदाता सूचियां में हो सकती है और अवैध रूप से भारत में रह रहे घुसपेठिया ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिया हो।

मतदाता सूची का निर्माण व समय-समय पर उसको अपडेट किया जाना नितांत आवश्यक है और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया होना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा इतने लंबे समय बाद पुनरीक्षण किया जाना विपक्ष द्वारा शंका के दायरे में आ गया है। जिसके बाद बिहार में एस आर आई को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। लेकिन अब पूरे देश में हो रही इस कार्रवाई को लेकर भी विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा सकता है। जिसके लिए चुनाव आयोग द्वारा विपक्ष की हर शंका का समाधान किया जाना नितांत आवश्यक है। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितनी सरकार की आवाज को महत्व दिया जाता है। ऐसे में राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि, वे केवल विरोध के लिए विरोध न करें, बल्कि उचित बातों का समर्थन भी किया जाना चाहिए।

इस बार चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि, वह राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बुथ लेवल एजेंट का रिकॉर्ड भी रखेगा जो सामान्यतः संबंधित मतदान केंद्र का मतदाता होता है और एजेंट की राय को दल की राय माना जाएगा। राजनीतिक दलों के एजेंट के फोटो और मोबाइल नंबर आयोग अपने पास रखेगा, वहीं इन्हें सार्वजनिक भी किया जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों को चाहिए कि, वे चुनाव आयोग द्वारा की जा रही इस कार्रवाई में सहयोग करें। वही अगर राजनीतिक दलों को यह लगता है कि, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वे, अपने एजेंटों के माध्यम से तत्काल आपत्ति दर्ज करवाए लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित न रहे। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची शुद्धिकरण का जो अभियान एस आर आई के माध्यम से चलाना चाहता है उसको लेकर कुछ पुख्ता तैयारी भी की गई है। जिसमें आयोग का कहना है कि, एस आर आई के बाद कोई भी व्यक्ति दो जगह की मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाएगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो तुरंत उसका नाम पकड़ में आ जाएगा। तथा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने वाले मतदाता की पहचान करना भी आसान हो जाएगा।

वहीं आयोग का कहना है कि, चुनाव आयोग जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यालय से भी लिंक करने की कार्रवाई प्रारंभ करने वाला है। ताकि मृत मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा कर मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जा सके। ऐसे में आम भारतीय नागरिक को भी चाहिए कि वो चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली इस कार्रवाई में अपना सहयोग करें। तथा चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा मांगे जाने वाले समस्त दस्तावेज समय पर उपलब्ध करावे।

पाकिस्तान पर तंज : अवैध कब्जा छोड़िए और आतंकवाद को रोकिए

नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान की रग-रग में गद्दारी और खून खराबा भरा पड़ा है। भारत में दहशत फैलाने में अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा, हमारे क्षेत्र को लेकर लालच करने के बजाय उन्हें भारतीय क्षेत्र पर किया गया अवैध कब्जा खाली कर देना चाहिए और लाइफ सपोर्ट पर टिकी अर्थव्यवस्था, सैन्य प्रभाव में दबी राजनीति और उत्पीड़न के धब्बे लगे मानवाधिकार के रिकॉर्ड को सुधारना चाहिए। शायद वो तब ऐसा करें, जब उन्हें आतंकवाद बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकवादियों को पनाह देने और अपने ही लोगों पर विस्फोट करने से फुर्सत मिले तो।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिराह घाटी के मत्रे दारा गांव में अपने ही नागरिकों पर हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गये और सैकड़ों अन्य घायल हो गये। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह हमला 21 सितम्बर की रात को किया गया और कई स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने अपने चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों से गांव पर कम से कम आठ एलएस - 6 बम गिराये। ग्रामीणों का कहना है कि इस बमबारी से गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। बारूद से जले शव घरों और सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। इस हमले के पैमाने, लक्ष्य या वहां किसी आतंकवादी की मौजूदगी के बारे में आधिकारिक पाकिस्तानी सैन्य या सरकारी सूत्रों से फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है।

इससे पहले भी पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और बलूचिस्तान में नागरिकों पर किए अपने जुल्मों पर चुप्पी साधे रखती आई है। रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने परिसर पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई हमले के दावों का खंडन करते हुए कहा कि बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों में विस्फोट हो गया, जिससे 14 आतंकवादियों समेत 24 लोगों की मौत हो गई।

सीएम का पलटवार, गौ-हत्या पर कड़ा रुख

भोपाल। कांग्रेस ने गौ-मांस पर टैक्स को लेकर सरकार पर आरोप लगाए थे। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 सितंबर को कटंगी में जोरदार पलटवार किया। सीएम ने कहा, हमारी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। इसलिए हम गौ-हत्या की सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस का गौमाता से कोई लेना-देना नहीं है। दशकों पहले उन्होंने करपात्री महाराज और साधु-संतों पर गोलियां चलवाई थीं। डॉ. मोहन यादव ने बताया कि, सरकार ने गौ-पालकों को प्रति गाय 40 रुपये देती है और जो 25 गाय पालकर 40 लाख रुपये का निवेश करेगा, उसे 10 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में गौ-मांस टैक्स मुक्त है और गौ-हत्या पर सख्त कानून लागू है। सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनके अपने इतिहास में साधु-संतों की हत्या और राम मंदिर मामले में विरोध शामिल है। उन्होंने जनता से कहा कि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता गली-मोहल्ले आए तो उसका हिसाब चुकता करें। डॉ. मोहन यादव ने यह भी बताया कि सरकार ने कई ट्रक और गाड़ियां जब्त की हैं, जिनमें गौवंश की तस्करी हो रही थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार गौमाता के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएम-डोनाल्ड ट्रंप की जल्द हो सकती है मुलाकात

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव के बीच दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द आमने-सामने बैठकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया है कि ट्रंप भारत पर लगाये गये भारी शुल्क को कम करने के लिए तैयार हैं। यह शुल्क रूस से भारत की ऊर्जा खरीद के कारण लगाया गया था। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान रुबियो ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की और कहा कि भारत अमेरिका का बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी है, खासकर व्यापार, ऊर्जा और औषधि क्षेत्र में।

पश्चिम बंगाल में भारी बारिश, कई मौते

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मानसून विदाई की ओर है, लेकिन जाते-जाते भारी तबाही मचा रहा है। तेज बारिश के कारण अब तक दस लोगों की जान जा चुकी है और रेलवे यार्ड तक पानी भर गया है। हवाई, रेल और लोकल परिवहन प्रभावित हुए हैं, वहीं स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।

कोलकाता में कुछ घंटों में 330 मिमी से अधिक बारिश हुई, जबकि शहर और उपनगरों में औसतन 250 मिमी वर्षा दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया और बस-टैक्सी समेत अन्य सार्वजनिक परिवहन ठप हो गए।

राज्य सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 और 25 सितंबर को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि अभूतपूर्व आपदा जैसी स्थिति बनी है और छात्रों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में और भारी बारिश हो सकती है। पूर्व-मध्य और उत्तरी बंगाल में 25 सितंबर के आसपास नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है।

कांग्रेस की बैठक संपन्न, महागठबंधन सरकार का किया दावा

पटना, एजेंसी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। करीब साढ़े चार घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने कई प्रस्ताव पारित किए और साफ संकेत दिए कि दो महीने के भीतर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।

बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और सचिन पायलट जैसे नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जैसे तेलंगाना में कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, वैसे ही बिहार में भी बदलाव तय है।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि, केंद्र और राज्य की सरकारें बेरोजगारी, किसान और बाढ़ जैसे मुद्दों पर विफल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की तरह देशभर में मतदाता सूची से छेड़छाड़ की साजिश हो रही है, जिससे गरीब और वंचित वर्गों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हैं और महागठबंधन की राह साफ है। पार्टी ने संकल्प अभियान के जरिए जनता से सक्रिय सहयोग की अपील की है।

दावा: नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार होने के पहले दिन बाजार में आई रौनक

नई दिल्ली, (ईएमएस)।

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार लागू होने के पहले दिन बाजार में रौनक देखने को मिली और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्राप्त हुई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉ. संबित पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्र और दुर्गा पूजा के अवसर पर जीएसटी में कटौती ने पूरे देश में त्यौहार जैसा माहौल बना दिया है।

उन्होंने बताया कि मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा जैसी वाहन कंपनियों में बिक्री का रिकॉर्ड टूटा है जबकि मोटरसाइकिल और छोटे वाहन भी बड़ी मांग में हैं। जीएसटी कटौती का असर दवाओं पर भी पड़ा है, जिससे शुगर, रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयों पर बड़ी राहत मिली।

उन्होंने कहा कि कपड़े, जूते, शीतलन यंत्र (एसी), धुलाई मशीन (वॉशिंग मशीन), एलईडी और अन्य उपकरणों की कीमतों में भी गिरावट आई है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ हुआ है।

भाजपा सांसद ने विभिन्न शहरों के उदाहरण देते हुए बताया कि लोग खरीदारी में छूट के कारण बेहद खुश हैं और जीएसटी सुधार से देश में उत्साह का माहौल है।

डॉ. पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस आकांक्षी भारत की बात की है, उसका सीधा उदाहरण वाहन बाजार में देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी ने कार बुकिंग का पिछले 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हुंडई के विक्रय केंद्र में भी 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है।

जीएसटी दरों में कटौती के पहले ही दिन, यानी कल मारुति ने 25,000 कारों की आपूर्ति की। मारुति के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पार्थो बनर्जी ने कहा कि यह वास्तव में ऐतिहासिक क्षण है। पिछले 35 वर्षों में पहली बार देखा गया है कि पहले ही दिन 80,000 पूछताछ दर्ज हुईं और 25,000 से अधिक कारें उपलब्ध करा दी गईं। उन्होंने बताया कि आपूर्ति जल्द ही 30,000 तक पहुँच जाएगी।

कंपनी को पहले ही दिन 75,000 से 85,000 बुकिंग प्राप्त हुईं और अब लगभग 50,000 नई बुकिंग प्रतिदिन आ रही हैं, जो पहले से 50 प्रतिशत अधिक है। हर दिन औसतन 15,000 मारुति कारों की बुकिंग हो रही है। यही नहीं, महिंद्रा, हुंडई, टाटा जैसी कंपनियों में भी ग्राहकों के बीच जबरदस्त आकर्षण देखने को मिल रहा है।

चैतन्यानंद के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज

नई दिल्ली, (ईएमएस)। दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज स्थित एक आश्रम में चल रहे निजी प्रबंध संस्थान के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया है। चैतन्यानंद पर पूर्व में भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। पूछताछ के दौरान संस्थान की 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़छाड़ व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए थे। शारदा प्रबंध संस्थान की छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

संस्थान के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। यह संस्थान शारदा पीठ शृंगेरी से जुड़ा हुआ है। पीए मुरली की ओर से वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि शारदा प्रबंध संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. स्वामी पार्थसारथी ने यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित छात्राएं ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति के तहत स्नातकोत्तर प्रबंधन डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रही हैं। पीड़िताओं के बयान न्यायिक दंडाधिकारी के सामने दर्ज कराए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की आखिरी स्थिति आगरा के पास पाई गई थी और उसकी तलाश जारी है। घटना के बाद शारदा संस्थान और शृंगेरी मठ प्रशासन ने आरोपी को सभी पदों से हटा दिया है और उससे संबंध समाप्त कर दिए हैं। शारदा पीठम ने आरोपी की गतिविधियों को अवैध, अनुचित और संस्थान के हितों के विपरीत बताया है।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 75(2), 79, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान बंद परिपथ कैमरा (सीसीटीवी) फुटेज की जांच की गई, घटनास्थल और आरोपी के पते पर छापे मारे गए, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। पुलिस ने संस्थान के तहखाने में खड़ी एक वोल्वो कार जब्त की, जिस पर फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट (39 यूएन 1) लगी थी और जिसे आरोपी इस्तेमाल करता था। इस संबंध में 25 अगस्त 2025 को नया मामला दर्ज किया गया और कार जब्त कर ली गई।

पुलिस ने संस्थान से सीसीटीवी फुटेज जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी है। पुलिस के अनुसार, 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अश्लील संदेश भेजे और अवांछित शारीरिक संपर्क बनाया। पीड़िताओं ने यह भी बताया कि संस्थान की कुछ महिला प्राध्यापिका और प्रशासनिक कर्मचारी उन्हें आरोपी की मांगों को मानने के लिए दबाव डालती थीं।

व्यवस्था पर कटाक्ष :

शराब ठेकेदार के लोगों पर नहीं है किराए पर रहने वाले लोगों की जानकारी के नियम

शराब ठेकेदार के लोग क्षेत्र में घूम-घूम बहा रहे शराब पीने व पिलाने वाली ज्ञान की गंगा

माही की गूंज, झाबुआ।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग-अलग कानून बने हुए है, उसमे से एक है किसी भी मकान में किराए से रहने वाले व्यक्ति की जानकारी विगत संबधित थाने या चौकी में देनी होती है। विगत दिनों थांदला में कई राज्यों में अपराधो में शामिल सलमान लाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद जिले में कई जगहो पर सामाजिक और हिंदू संगठनों ने ज्ञापन देकर बाहरी लोगो के द्वारा किराए से रहने वाले लोगो की जानकारी लेने की मांग पुलिस और प्रशासन की थी। हालाकि ये कानून केवल आम लोगो पर लागू है। जिनको अपने घरों में किराए से रहने वाले लोगो की जानकारी देनी होती है और उसके आधार पर प्रशासन और पुलिस उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाते है, जिससे किसी बड़े अपराधी या अपराधिक छवि वाले व्यक्ति की जानकारी मिल सके। पर ये कानून क्षेत्र के शराब ठेकेदार पर लागू नही होता है। जबिक इन ठेकेदार के पास कई लोग काम करते है जिसमे से अधिकाश कर्मचारी बाहरी राज्यों के होते है और उनकी भाषा और व्यवहार सामन्य न होकर बिल्कुल गुंडा तत्वों जेसी होती है।

एक दुकान पर दो से तीन कर्मचारी रखने का नियम

शराब ठेकेदार को शासन के नियमानुसार शराब की दुकान पर मात्र दो से तीन लोगो को कर्मचारी के रूप में रखने का नियम है। जिसका नियमानुसार नोकरनामा लिखाकर आबकारी विभाग में देना होता है। ठेकेदार खानापूर्ति के लिए आबकारी विभाग में कर्मचारियों के नोकर नामें पेश किए हुए है। लेकिन बिना नोकरनामे बदले ही शराब की दुकानों पर कर्मचारी बदले जाते है। हालाकि नियम के विपरित शराब ठेकेदार दो-तीन नही कई कर्मचारियों को काम पर रखे हुए है जो स्थानीय नही होकर अन्य राज्य खास कर यूपी और बिहार राज्य के है। इनको कोई जानकारी शराब ठेकेदार द्वारा आबकारी और पुलिस विभाग को नही दी जाती है।

कोन लोग है कोई नही जानता ,अपराधिक छवि की जानकारी भी नहीं

क्षेत्र शराब ठेकेदार के लिए जो लोग काम कर रहे है उनकी कोई जानकारी नहीं है की वो कोन लोग है और कहा से आए है और इनकी आपराधिक पृष्ठ भूमि की भी कोई जानकारी पुलिस और आबकारी के पास नहीं है। ये लोग दिन और रात ऐसे घूमते है जैसे क्षेत्र में शराब से संबंधित पिने-पिलाने की ज्ञान की गंगा बहा रहे हो। और ये कोई बड़ा महान कार्य कर शराब

ठेकेदार के ये अवैध कर्मचारी शराब ठेकेदार के लिए क्षेत्र में अवेध शराब सप्लाई करने, बहार के क्षेत्र से अवेध रूप से शराब बेचने वालो की जानकारी निकालने का काम करते है। यहां तक की कई बार आबकारी और पुलिस का काम भी शराब ठेकेदार के लोग करने लग जाते है और अवैध शराब की सूचना पर ठेकेदार के लोग जानकारी के आधार पर अवैध वाहनों के पीछे लग जाते है। शराब पकड़े जाने की स्थिति में ठेकेदार के लोग सहुलियत के अनुसार पुलिस या आबकारी विभाग को शामिल कर शराब पकड़ना बता देते है। बताया जा रहा है, शराब ठेकेदार के ये अवैध कर्मचारी क्षेत्र भर में दिन और रात में बेफिक्र होकर गस्त करते है इनके पास जो वाहन होते है उनकी जानकारी तक जिम्मेदारो के पास नही होती है सूत्र बताते है कि, इनके पास अवैध हथियार तक होते है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रो में शराब ठेकेदार की शराब की गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्रो में रोक ली जाती है वहा भी ठेकेदार के ये अवैध लोग तुरंत मौके पर पुलिस और आबकारी से पहले पहुंच जाते है।

पूर्व में हो चुका है हत्या जैसा गंभीर अपराध फिर भी नहीं होती पूछताछ

लगभग 6 से 7 वर्ष पूर्व रायपुरिया में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों के आपसी विवाद के चक्कर में शराब ठेकेदार के मैनेजर की हत्या उसके साथियों ने ही आफिस में कर दी थी। हत्या जैसा गंभीर अपराध होने के बाद भी प्रशासन ने ठेकेदार द्वारा रखे गए कर्मचारियों की जानकारी पुलिस द्वारा आज तक नही ली जाती। जिन लोगो के मकान किराए से होते है उनका एग्रीमेंट भी शराब ठेकेदार या उसके मैनेजर के नाम से होता है। लेकिन उस मकान में कोन आता है, कोन जाता है इसकी कोई जानकारी मकान मालिक तक को नहीं होती है। शराब ठेकेदार के पास शराब दुकानो पर 2-3 कर्मचारियो के अलावा हर दुकान ग्रुप क्षेत्र में स्थित आफिसो में बडी संख्या में कर्मचारी रहते है। इनमे से कईयों के पास बंदूके भी होती है जो की लाइसेंसी है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए और पुलिस रिकॉड भी होना चाहिए। शराब ठेके पर आए दिन विवाद की स्थिति बनती है और उससे निपटने के लिए भी शराब ठेकेदार को पुलिस और आबकारी विभाग की आवश्कता नही है। ठेकेदार के ये अवैध गुर्गे ही मामला निपटा देते है। सब से बडी बात यह की यह शराब माफिया किसी के नही हुए है यानी जो जो प्रशासन के नुमाईदे पैसा लेकर इन्हे संरक्षण दे उन्ही पर भी मोका आने पर जान लेवा हमला तक अपने अवैध व्यवसाय को बचाने के लिये व आतंक को कायम रखने के लिये कर देते है। जिसके कई उदाहरण आदिवासी बाहुल आलिराजपुर जिले व झाबुआ जिले में देखे गए है जिसमें शराब ठेकेदार के इन्ही अवैध गुर्गो ने पुलिस व प्रशासन पर जान लेवा हमले करे है वाहनो को जलाया है। बावजुद अपना जमीर बेच शराब माफियाओं के सामने नतमस्तक होकर पुलिस व प्रशासन इनके इतने पंगु बने हुए कि, शराब माफिया के झाबुआ जिले में ही करिब 500 कर्मचारी बाहरी है जो आपराधिक पृष्ठभूमि के भी है पर उनकी जानकारी रखना शायद पुलिस नियम में नही आता है।

संघ शताब्दी वर्ष पर विशेष पथ संचलन का हुआ आगाज

माही की गूंज, खवासा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को खवासा खंड के भामल मंडल में विशेष पथ संचलन एकत्रीकरण का आयोजन किया गया। एकत्रीकरण के बाद स्वयंसेवक घोष वादन और कदमताल के साथ गांव की मुख्य गलियों से गुजरे।

कार्यक्रम में जिले के सह जिला कार्यवाह संतोष निनामा ने बौद्धिक उदबोधन दिया। उन्होंने संघ शताब्दी वर्ष के नियमित होने वाले पंच परिवर्तन पर विस्तृत जानकारी साझा की और संगठन के कार्य विस्तार पर स्वयंसेवकों को प्रेरित किया।

खनिज विभाग की अवैध उत्खनन पर कार्यवाही, 33,61,590 का जुर्माना

माही की गूंज, झाबुआ। खनिज अधिकारी जुवानसिंह भिडे, प्रभारी खनिज निरीक्षक (सर्वेयर) श्रीमती आलिशा रावत एवं खनिज अमले ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्राम बिलीडोज (झाबुआ) सर्वे नं. 133, 137 पर मोरम खनिज का अवैध उत्खनन करते पाया गया। जिसपर अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध कर जैन डेवलपर संचालक मनोहरलाल छाजेड निवासी पारा एवं दिपक भण्डारी निवासी जगमोहनदास मार्ग झाबुआ के विरूद्ध अर्थदण्ड राशि 33,61,590 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

परिवहन परिपत्र में अंकित मात्रा से अधिक अवैध परिवहन करते पाये जाने पर ओवरलोड का 1 प्रकरण पंजीबद्ध कर राशि 15209 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

घटस्थापना के साथ ही शक्ति की भक्ति का महापर्व प्रारंभ

माही की गूंज, खवासा।

सोलह दिनों तक अपने पितरो को याद करने के बाद शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा का महापर्व शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होता है जिसको लेकर सभी उत्साहित रहते हैं। इसकी तैयारीया कई दिनों पूर्व से प्रारंभ हो जाती है और अब यह त्यौहार अंचल का बड़ा त्यौहार बनता जा रहा है। गांवो और शहरों में समान रूप से यह त्यौहार बड़े उत्साह व उमंग के साथ मनाया जाता है। इन नौ दिनों में व्रत भी रखा जाता है, जाप भी किया जाता है और गरबा व रास के माध्यम में देवियों की आराधना भी की जाती है। खवासा सहित आसपास के सभी गांवो में घट स्थापना के साथ ज्वारे भी बोय जाते हैं। साथ ही कई जगह पावागढ़ से ज्योति लाकर अखंड ज्योति की स्थापना भी की जाती है। ज्वारे से आगामी रबी की फसल का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। खवासा के प्राचीनतम तथा चमत्कारी रोग्यादेवी मंदिर पर 50-60 वर्षों से अधिक समय से गरबा कार्यक्रम होता आ रहा है। इस वर्ष रोग्यादेवी मित्र मंडल के तत्वाधान में प्रथम दिवस विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में महिला-पुरुष एक जैसी वेशभूषा में शामिल हुए। चुनरी यात्रा पूरे गांव में भ्रमण के पश्चात पुनः रोग्यादेवी मंदिर पहुंची। जहां विधि विधान से पूजन अर्चन कर माताजी की मूर्ति स्थापित की गई। यहां प्रतिदिन रात्रि में म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग गरबो की प्रस्तुति दी जाती है। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं गरबा के माध्यम से माँ की आराधना करती है। यहां महिला मंडल द्वारा प्रतिदिन के लिए एक जैसा ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है।

वहीं हनुमान मंदिर पर संकट मोचक मित्र मंडल द्वारा गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें म्यूजिकल ग्रुप द्वारा गरबा की प्रस्तुतियां दी जा रही है। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही है।

युवा सफलता की मिसाल बनें-कलेक्टर

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत घोषित परिणामों में जिले के ग्राम काकरादरा निवासी विकेश मचार का चयन उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद के लिए हुआ है। इस उल्लेखनीय सफलता पर कलेक्टर ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं एवं इस उपलब्धि को झाबुआ जिले के लिए गर्व का विषय बताया। अपर कलेक्टर सीएस सोलंकी ने भी श्री मचार को पुष्पमाला पहना कर बधाई दी।

भेंट के दौरान कलेक्टर ने कहा कि, विकेश मचार जैसे युवाओं की सफलता यह सिद्ध करती है कि, कठिन परिश्रम, लगन और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि झाबुआ जैसे जनजातीय बाहुल क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है तो केवल उचित मार्गदर्शन, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास की।

भाजपा की जिला कार्यकारणी की घोषणा, पेटलावद को नही मिला महामंत्री पद ,थांदला को किया मजबूत

माही की गूंज ,झाबुआ।

कई दिनों से भाजपा की जिला कार्यकारणी की घोषणा की चर्चा जोरो पर थी। बुधवार देर शाम को जिला कार्यकारणी की घोषणा हुई जिसने कई नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया। ज्यादातर नाम पर भाजपा नेताओं को उम्मीद नहीं थी। नई कार्यकारणी में कई पुराने चेहरे शामिल है तो बाकी नए चेहरों के साथ नए लोगो को मोका दिया गया। कार्यकारणी में पेटलावद विधानसभा के हिस्से में इस बार महामंत्री पद नही आया। जबकि थांदला विधानसभा से ज्यादा नेताओ को मोका मिला है। महामंत्री पद के पेटलावद विधानसभा से मंत्री भूरिया के खास हेमंत भट्ट का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन उनको उनके पुराने उपाध्यक्ष पद से संतुष्ट होना पड़ा। दुर्गादास राठौड़ जो की पूर्व में मंत्री थे इस बार उपाध्यक्ष बनाए गए। कोषाध्यक्ष पद पर महावीर भंडारी के खाते में दूसरी बार गया। थांदला विधानसभा से संजय भाबर का नाम महामंत्री के लिए तय माना जा रहा था लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ और भाजपा ने थांदला विधानसभा को मजबूत करने के लिए पद ज्यादा दिए और दोनो महामंत्री थांदला से देते हुए राजेश वसुनिया और पूर्व महामंत्री गौरव खंडेलवाल को दोबारा इसी पद पर मोका मिला। झाबुआ से सत्येंद्र यादव महामंत्री की रेस थे लेकिन उनको पुराने उपाध्यक्ष पद से संतुष्ट होना पड़ा। विजय चौहान को झाबुआ विधानसभा से विजय चौहान को महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। नई कार्यकारणी को लेकर नाराजगी होना तय है क्योंकि निर्मला भूरिया के विधानसभा क्षेत्र से किसी आदिवासी नेता को मोका नहीं मिला। सूची में ज्यादातर नाम सामान्य और ओबीसी वर्ग से है। थांदला से कलसीह भाबर के पुत्र संजय भाबर का नाम गायब होना चौकाने वाला है। आने वाले दिनों में कार्यकारणी पर जबरजस्त राजनीती देखने को मिलेगी।

वही सुची में उपाध्यक्ष रामेश्वर नायक,समर्थ उपाध्याय, मदन भूरा, श्रीमति माया सोंलकी, श्रीमति आरती भानपुरिया। मंत्री लालचन्द गाहरी, दिपेश सकलेचा,श्रीमति सुनिता भूरिया, श्रीमति इंदुबाला डामोर, जगदिश बडदवाल, श्रीमति सुभद्रा पाटीदार। कार्यालय मंत्री मनोहर मोदी, सःकार्यालय मंत्री रजनिश गामड़। सह कोषाध्यक्ष, अर्पित कटकानी की नियुक्ती की गई।

डिजिटल इंडिया में पिछड़ता प्रदेश, एआई के दौर में प्रदेश की 59 हजार विद्यालया कम्प्यूटर विहिन

माही की गूंज, झाबुआ।

शिक्षा की जागृति और परिवर्तन के परिवेश में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होकर शिक्षा के अलख को जगाए रखना ही संसार के साथ चलना होता है, अन्यथा कुछ कदम पीछे हुए तो बहुत पीछे रह जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहने का अर्थ है विकास की गति को धीमें कर देना। क्योंकि भावी पीढ़ी शिक्षा के उस स्तर को छु नहीं पाएगी जहां अन्य देश पहुंच गए है। ऐसी ही स्थिती मध्य प्रदेश में सामने आई है जहां एआई के दौर में तेजी से आगे बढ़ती दुनिया और पिछड़ता हुआ प्रदेश दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के करीब 59 हजार स्कूल में कम्प्युटर नहीं है, और अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, के जवाब गैर जिम्मेदाराना आ रहे हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रक्ट इंफारमेशन सिस्टम फार एजुकेशन (युडाइस) द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2024-2025 की रिपोर्ट ने प्रदेश में डिजिटल इंडिया की सच्चाई सामने लाते हुए जांच प्रस्तुत की है। जिससे पता चलता है कि, प्रदेश में एआई की शिक्षा को देने के लिए जो पाठ्यक्रम लागु किया था उसे संचालन करने में प्रदेश पूरी तरह से पिछड़ा साबित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेशभर में ऐसे 59,797 स्कूल है जहां पर कम्प्युटर पहुंचे ही नहीं है। इन सारे कम्प्युटर का बजट कहां गया, किसने उसे समाप्त किया इस पर मंत्री और जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे है। रिपोर्ट में और भी बहुत से खुलासे हुए है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि, मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिती अत्यंत दयनिय है, और मामला इतना गंभीर है कि एआई की शिक्षा से वंचित होते विद्यार्थी तेजी से आगे बढ़ती कम्प्युटर की दुनिया में बहुत पीछे शर्म से सर झुकाए खड़े है। रिपोर्ट में और भी आंकड़े है जो जारी किए गए है वो चौकाने वाले है लेकिन इतनी कमी बताने पर भी उन जिम्मेदारो की आंखों में लाज, शर्म नाम की कोई चिज नहीं है और सरकार का पैसा खा कर लोग डकार भी नहीं लेते।

रिपोर्ट के अनुसार 10,800 ऐसे स्कूल है जहां बिजली पहुंची ही नहीं है, और बड़े ही शर्म की बात है 15 हजार के करीब ऐसे स्कूल है जहां बिजली की आपूर्ति नहीं है। प्रदेश सरकार शिक्षा की जागृति के दावे तो बड़े-बड़े करती है मगर धरातल पर सुविधाए रेगती भी दिखाई नहीं देती। क्या प्रदेश सरकार द्वारा बिजली सुविधा या बिजली आपूर्ति के लिए कभी कोई बजट नहीं पास किया गया होगा...? और यदी किया है तो वह बजट आखिरकार कहा गया...? प्रदेश के बच्चें जिन्हें पढ़-लिख कर समाज को उच्च और श्रेष्ठ बनाना है उन्हें सुविधाओ से दूर रखा जा रहा है। जबकि सरकार द्वारा उनके लिए पर्याप्त बजट दिया जा चुका है।

66 हजार 255 स्कूल जहां इंटरनेट नहीं है, अब कैसे विद्यार्थी डिजिटल इंडिया की नीव को शक्तिशाली कर पाएगे। 2301 विद्यालय बिना लाइब्रेरी के चल रहे हैं। वहीं 1 लाख 19 हजार 412 स्कूल जहां डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। 6213 स्कूल में खेल का मैदान नहीं है। 564 विद्यालय जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। 1365 विद्यालय जहां पीने के पानी की सुविधा तक नहीं है और ऐसे में कैसे मध्यप्रदेश का विद्यार्थी शिक्षा का उचित अध्ययन कर उच्च शिक्षित होगा...? भूलती जा रही है। जो रिपोर्ट इस वर्ष आई है उसमें जितनी कमियां पाई गई है क्या वो सारी कमी सिर्फ एक वर्ष की कमियां लगती है...? जवाब नहीं बिल्कुल भी नहीं।

प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार कर अपने लाभ के लिए प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनके शिक्षा के अधिकार का हनन कर रही है, और इन सब में भागिरदार प्रदेश का प्रशासनिक अमला भी शामिल है। जिसके कारणवश प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरते ही जा रहा है प्रत्येक असुविधाओ में शिक्षा कैसे फलीभूत होकर विकासशील होगी इसका उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है।

4 हजार से ज्यादा स्कूल ऐसे है जहां बालिकाओ के लिए शौचालय नहीं है। अन्य 5 हजार स्कूल जहां बालको के लिए शौचालय नहीं है। 39 हजार से ज्यादा विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं है। गंभीर बात तो यह है कि, ऐसे 10 हजार से ज्यादा स्कूल है जहां अभी तक बिजली नहीं है। रिपोर्ट के आंकड़ो को देखते हुए तो लगता है कि, प्रदेश सरकार शिक्षा के नाम का पैसा अपनी जैब में रख कर वर्ष शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए बजट जारी किया जाता है। मगर उसका उपयोग भ्रष्टाचारियों में बंट जाता है और बच्चें असुविधा की झोली ढोते हुए अगले दिन के सवेरे की प्रतिक्षा करते ही रह जाते हैं।

रिंकेश बैरागी

प्रदेश में इतनी बुरी तरह से शिक्षा के आंकड़े सामने आएगें जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। सरकारी विद्यालयों में इतनी असुविधाओ के कारण ही प्रदेश के बच्चें शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूरी में आकर निजी स्कूलों में जा कर अधिक से अधिक फीस जमा कर पढ़ते है और उनके माता-पिता कर्जा लेकर उस फीस को भरते हैं।

बहरहाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रक्ट इंफारमेशन सिस्टम फार एजुकेशन (युडाइस) द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2024-2025 की रिपोर्ट ने इतना तो साबित कर ही दिया कि, प्रदेश में शिक्षा का स्तर और उसमें सुविधा का स्तर धुमिल है। अब शिक्षा मंत्रालय को इस बात की भी जांच करनी होगी कि, प्रदेश सरकार द्वारा जो भी बजट शिक्षा और उसकी गुणवत्ता या विद्यालय की सुविधाओ को बढ़ाने के लिए जारी किया गया उस बजट का बंटवारा कहां-कहां हुआ। उसके बाद उन सभी भ्रष्टाचारियों से 10 गुना अधिक वसुली की जाए। साथ ही साथ उन्हें सजा भी दी जाए, ताकि फिर कभी कोई बच्चों की शिक्षा और सुविधा का पैसा अपनी जेब में न रखे।

सूचना अधिकार में अपने घर के नियम चलाते अधिकारी, मांगी गई जानकारी से ज्यादा जानकारी आखिर क्यों...?

बड़ा बिल थमा कर दबाओ बनाने की कोशिश में अतिरिक्त जानकारी दे रहे बीईओ साहब

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

राइट टू इन्फोर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के तहत कानून के दायरे में आने वाली सरकारी जानकारी, प्रमाणित दस्तावेज , अवलोकन करने का अधिकार आम जन को आता है। उक्त कानून के लागू होने के बाद से बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए है और कई ऐसी जानकारियां बहार आई है जिसको लेकर झूठ परोसा जाता है। लेकिन रिकॉड में कुछ और ही दर्ज होता है। कानून आम जनता के लिए इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी जानकारी सार्वजनिक हो सके और भ्रष्टाचार व अनियमित्ताओ पर अंकुश लगे। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है सूचना अधिकार अधिनियम कानून कई बड़े संस्थानों, नेताओ और सप्लायरो के लिए गले की हड्डी बन चुका है तो एक वसूली का बड़ा साधन भी बन चुका है। इसलिए उक्त कानून ने कई प्रकार के फेर बदल भी सरकार द्वारा किए है। सरकारी फेर बदल तक तो ठीक है लेकिन अलग-अलग विभाग के अधिकारी उक्त कानून को अपने हिसाब से फेर-बदल कर या कानून में दर्ज नियम के अलावा खुद के नियम लगा कर जानकारी मांगने वालो पर दबाब बनाते हुए अलग-अलग कारणों से कभी आवेदन निरस्त ,तो कभी सरकारी रिकॉड को निजी जानकारी बता कर, तो कभी गलत जानकारी मांगना बता कर आवेदन को फाइलों में घुमाया जाता है। मामला पेटलावद विकास खंड का है जहा जानकारी को बहार आने से रोकने के लिए या आर्थिक भार दिखा कर जानकारी को दबाया जा रहा है।

चाही गई जानकारी से अतिरिक्त जानकारी

विगत दिनों पेटलावद विकास खंड में हुई अतिथि शिक्षको की भर्ती में हेरा-फेरी और अलग-अलग अभ्यर्थियो द्वारा नियुक्ति नहीं होने के चलते हेरा-फेरी का आरोप लगा शिकायते एसडीएम स्तर से लेकर सीएम हेल्प लाइन तक हुई है। उक्त भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार की हेरा-फेरी हुई या नही हुई इसकी जानकारी के लिए पेटलावद विकास खंड में हुई अतिथि भर्ती हेतु की गई कार्यवाही के प्रमाणित दस्तावेज, सूचिया आरटीआई कानून के तहत खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से मांगी गई। जानकारी सामान्य होकर केवल संकुल स्तर से हुई नियुक्ति की थी लेकिन खुद के द्वारा पूरे नियमो का हवाला देकर की गई नियुक्तियों में बीईओ साहब को भरोसा नहीं होना दिखाई पड़ता है और जानकारी नही देने के अलग-अलग रास्ते निकालने की कोशिश करने लगे। जब कोई युक्ति काम नहीं आई तो चाही गई जानकारी के एवज में एक पत्र, जानकारी मांगने वाले को जारी कर चाही गई जानकारी के लिए फोटो कॉपी की राशि का भुगतान करने का पत्र भेजा। जिसमे

:: कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, (जनजातीय कार्य विभाग) पेटलावद ::
E-Mail I.D. - beopetlawad10@gmail.com

क्रमांक/सु.अधि./2025/2043 पेटलावद, दिनांक 08/09/2025

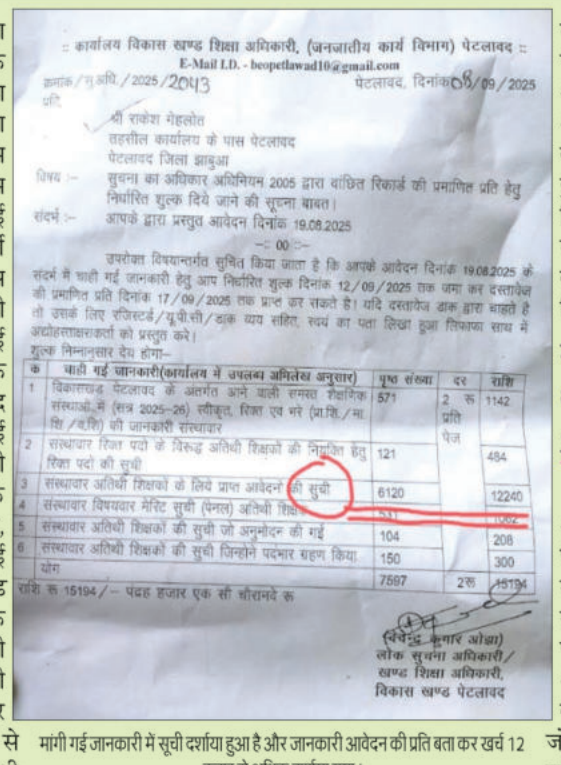

प्रति,
श्री राकेश गेहलोत
तहसील कार्यालय के पास पेटलावद
पेटलावद जिला झाबुआ

विषय :- सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा वांछित रिकार्ड की प्रमाणित प्रति हेतु निर्धारित शुल्क दिये जाने की सूचना बाबत।

संदर्भ :- आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.08.2025

-:: 00 ::-

उपरोक्त विषयान्तर्गत सुचित किया जाता है कि आपके आवेदन दिनांक 19.08.2025 के संदर्भ में चाही गई जानकारी हेतु आप निर्धारित शुल्क दिनांक 12/09/2025 तक जमा कर दस्तावेज की प्रमाणित प्रति दिनांक 17/09/2025 तक प्राप्त कर सकते है। यदि दस्तावेज डाक द्वारा चाहते है तो उसके लिए रजिस्टर्ड/यू.पी.सी/डाक व्यय सहित, स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे।

शुल्क निम्नानुसार देय होगा–

क्र	चाही गई जानकारी(कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार)	पृष्ठ संख्या	दर	राशि
1	विकासखण्ड पेटलावद के अंतर्गत आने वाली समस्त शैक्षणिक संस्थाओ में (सत्र 2025-26) स्वीकृत, रिक्त एवं भरे (प्रा.शि./मा.शि./उ.शि) की जानकारी संस्थावार	571	2 रू प्रति पेज	1142
2	संस्थावार रिक्त पदो के विरूद्ध अतिथी शिक्षको की नियुक्ति हेतु रिक्त पदो की सुची	121		484
3	संस्थावार अतिथी शिक्षको के लिये प्राप्त आवेदनों की सुची	6120		12240
4	संस्थावार विषयवार मेरिट सुची (पेनल) अतिथी शिक्षक	531		1062
5	संस्थावार अतिथी शिक्षकों की सुची जो अनुमोदन की गई	104		208
6	संस्थावार अतिथी शिक्षकों की सुची जिन्होने पदभार ग्रहण किया	150		300
	योग	7597	2रू	15194

राशि रू 15194/– पंद्रह हजार एक सौ चौरानवे रू

(विरेन्द्र कुमार ओझा)
लोक सुचना अधिकारी/
खण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकास खण्ड पेटलावद

मांगी गई जानकारी में सूची दर्शाया हुआ है और जानकारी आवेदन की प्रति बता कर खर्च 12 हजार से अधिक दर्शाया गया।

साहब ने चाही गई जानकारी से अतिरिक्त जानकारी अपनी ओर से देने की कोशिश करते हुए फोटो कॉपी के बिल को तीन हजार से सीधा पंद्रह हजार के ऊपर पहुंचा दिया।

मांगी सूची थमाए जा रहे आवेदन

सूचना के अधिकार में पेटलावद विकास खंड के समस्त संकुलो में अतिथि पद के लिए आए आवेदनों की सूची की मांग की गई थी जो की प्रति संकुल दो या तीन पेज में तैयार की जा सकती है। लेकिन यहां बीईओ साहब ने अपना अतिरिक्त दिमाग लगाया और जानकारी देने के लिए इतना खर्च बढ़ाया की जानकारी लेने वाले को सोचना पड़े और अथितियो के आवेदन की सूची की बजाए पूरे संकुल में किए गए पूरे आवेदन की फोटो कॉपी जो की जानकारी में नहीं मांगी गई वो देने के नाम पर कुल 6120 प्रति का कुल भुगतान 12,240रुपए का बिल अन्य जानकारियों की प्रति का बिल मिला कर 15,194रुपए का भुगतान चाही गई जानकारी के लिए करना बताया गया। अब साहब जानकारी देना नही चाह रहे या जानकारी अतिरिक्त देकर संकुल स्तर पर हुई हेराफेरी को खुद ही उजागर करना चाह रहे है ये तो साहब ही जाने।

सूची तैयार नहीं की इसलिए आवेदन की प्रति दे रहे है

वैसे तो शासन के पास मांगा गया कोई रिकॉड उपलब्ध नहीं होने की दशा में सीधे लिख कर दिया जाता है कि, चाही गई जानकारी उपलब्ध नही होने की जानकारी दी जाती है। लेकिन यहां मामला उल्टा हुआ। जो जानकारी उपलब्ध नही थी उसके लिए उपलब्ध नही है लिखने की जगह उस जानकारी से जुड़े महत्त्वपूर्ण दस्तावेज देने के प्रयास किए जा रहे है जो सीधा सीधा सूचना अधिकार अधिनियम कानून का उलंघन है। जानकारी मांगने वाले ने साहब से जब अतिरिक्त जानकारी देने पर पूछा तो साहब ने बताया कि, अथितियों के आवेदनों की कोई सूची तैयार नही की गई इसलिए आवेदन की प्रति उपलब्ध करवाई जा रही है, यहां तक की साहब ने आगे अपील करने तक की बात कह दी।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहे है सवाल

विकास खंड में हुई अतिथि शिक्षको की भर्ती में भारी हेराफेरी होने की आशंका है। कई वर्षो से कार्यरत अतिथि शिक्षको को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, कई स्थानों पर नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षको की भर्ती हुई है। जिसकी प्रमाणित पुष्टि के बाद गूंज की कलम से भंडाफोड़ किया जाएगा जिसके लिए प्रमाणित जानकारी का इंतजार है। अधिकारी नियमो में अपने कानून डाल कर कब तक जानकारी देने से बचते रहेंगें... !

गूंज असर: ग्राम पंचायत भेरूगढ़ की रामगढ़ फलिया में अब ग्रामीणों को मिलने लगा पानी

ट्यूबवेल में पर्याप्त मात्रा में पानी पर जल जीवन मिशन में बनी पानी की टंकी से नहीं मिल रहा पानी

पिछले अंक में प्रमुखता से प्रकाशित समाचार ।

माही की गूंज, खवासा।

थांदला जनपद क्षेत्र के खवासा क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली भेरूगढ़ ग्राम पंचायत का बड़ी रामगढ़ फलिया में जल जीवन जल मिशन में बनी पानी की टंकी 3 साल से बंद पड़ी हुई थी। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए माही की गूंज ने प्रमुखता से इस समस्या को उठाया था। जिसके बाद पीएचई विभाग के अधिकारी व ग्राम पंचायत के जिम्मेदार सरपंच सचिव ने तत्परता से कार्य करते हुए टंकी की साफ-सफाई की गई। साथ ही सुबह व शाम को ग्रामीणों को दोनों ट्यूबल से पानी टंकी के माध्यम से फिलहाल दिया जा रहा है। आगे यह व्यवस्था निरंतर सुचारू रूप चलेगी या नही यह तो बाद में ही पता चलेगी।

समाचार के बाद नल के माध्यम से लोगों को मिला पानी।

ग्रामीणों ने माही की गूंज को धन्यवाद देते हुए कहा कि, हमारी समस्या काफी समय से थी जिसको आपने प्रमुखता से उठाया तथा ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जु रेंगी। उसके बाद ग्राम में पानी सप्लाई किया जा रहा है। आशा है कि, आगे भी इसी तरह ग्राम पंचायत के बड़ी रामगढ़ फलिया में पंचायत पानी सप्लाई करती रहेगी। उल्लेखनीय कि, जल जीवन जल मिशन के तहत ग्राम पंचायत बड़ी रामगढ़ में पानी की टंकी बनाई गई थी। उसके बाद 3 साल तक पानी की टंकी से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो वही ग्रामीणों ने बताया कि, काफी समय से नल की नलियां पर नल स्टैंड ना लगाते हुए नली ही ऐसे ही छोड़ दीं, ठेकेदार ने नल स्टैंड तक नहीं लगाए हैं वह एक समस्या अब भी बनी हुई है।

यहां सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि, जब ठेकेदार ने पूर्ण कार्य किया ही नहीं ना ही ग्रामीणों के घरों में नल स्टैंड लगाया तो आखिर ग्राम पंचायत को यह योजना कैसे हस्तांतरित हो गई? यह जांच का विषय है। क्योंकि पूरा कार्य होने के बाद ही टंकी को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जाती है। लेकिन यहां ठेकेदार ने अधूरा कार्य के साथ ही ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया जो एक जांच का विषय है।

विवेक मुलेवा नीट में चयनित, समाज ने दी बधाई

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद निवासी विवेक मुकेश मुलेवा नें इसी सत्र 2025 नीट सूची में स्थान बनाते हुए अच्छी रेंक के साथ निट क्वालिफाय करके सीर्वी समाज पेटलावद, स्कूल एवं माता पिता, पेटलावाद एवं मुलेवा परिवार का नाम रोशन किया। विवेक अब इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से डाक्टर की पढ़ाई करेगें। विवेक मुलेवा का चयन होने पर मित्रो और शूभचिंतको ने बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है।

सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ

माही की गूंज, पेटलावद।

सेवा के साथ स्वावलम्बन की दिशा में महिलाओं को ले जाना यह एक बडा कार्य है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल नौकरियां ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में स्कील डेवलप कर व्यवसाय के माध्यम से भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। महिलाओं को प्रशिक्षीत कर, उन्हें स्वावलम्बी बनाने के प्रयास में सभी महिलाओं को भी सहयोग करना चाहिए। उक्त बात विभाग सह कार्यवाह आकाश चौहान ने सेवा भारती झाबुआ प्रकल्प पेटलावद पर निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के शुभारंभ अवसर पर कहीं। चौहान ने सेवा भारती के अन्य प्रकल्पो जैसे बड़ा घोसलिया और झाबुआ के बारे में बताते हुए कहा कि, यहा के प्रशिक्षीत कई युवा आज अपना रोजगार चला रहे है जो की अच्छे उदाहरण है। हम पेटलावद प्रकल्प के माध्यम से भी ऐसे ही कई लोगों को रोजगार से जोडने का प्रयास करें। इस मौके पर सेवा भारती जिलाध्यक्ष हरिओम पाटीदार ने सभी से अपील की है कि, इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से जो भी प्रशिक्षण दिये जा रहे है। उनमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं और बालिकाओं को जोडा जाये और रोजगार उपलब्ध करवाया जाये। यहां आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षण में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाए। जिसमें मेहंदी, ब्यूटीपार्लर, सिलाई व कढाई बुनाई प्रशिक्षण मुख्य रूप से है। प्रकल्प पेटलावद पर महिला सशक्तिकरण के साथ बाल संस्कार केंद्र का भी संचालन किया जा रहा है। इस मौके पर सेवा भारती समिति के जिला सदस्य कृष्णा जाधव, सुरेश प्रजापति, निलेश सेन पूर्णकालिक कोमलसिंह निनामा,सिलाई प्रशिक्षक मधु बेन भायल सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र भट्ट ने किया।

संभाग दूरसंचार सलाहकार समिति सदस्य मनोनीत कटारिया

माही की गूंज, पेटलावद। भाजपा के युवा नेता प्रियांश कटारिया को संभाग क्षेत्र इंदौर दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस नियुक्ति की सूचना बीएसएनएल मुख्यालय के पत्र के आधार पर उप महाप्रबंधक व्यापार क्षेत्र इंदौर ने पत्र द्वारा दी गई। प्रियांश कटारिया की यह नियुक्ति रतलाम सांसद अनीता नागरसिंह चौहान के अनुशंसा पर की गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंदौर संभाग में सदस्य बनाए जाने पर प्रियांश कटारिया को भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनू विश्वकर्मा ने बधाई दी है। इस नियुक्ति पर अजय जैन, प्रदीप काग, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र काग, संजय बैरागी, रोहित चौधरी आदि साथियों ने सांसद चौहान, मंत्री नागर सिंह चौहान का आभार माना।

गरबों की धुम: 6 स्थानों पर माता रानी की स्थापना

माही की गूंज, पारा।

माता रानी के गरबा महोत्सव अवसर पर पारा ग्राम में छः स्थानो पर पांडाल सजे व माता रानी की घट स्थापना की गई। प्रथम सजनिया बस स्टैंड पर सार्वजनिक गरबा मंडल आयोजक कर्ता श्री रामायण मंडल व सार्वजनिक गणेश मंडल पारा द्वारा करवाया जा रहा । पिपली चौक, कुमार मोहल्ला ,होली चौक, केसर बाग चौराहा, श्री अंबे माता मंदिर बखतपुरा, व प्रथम वर्ष स्थानीय शनि मंदिर प्रांगण में आदि स्थानों पर पंडाल सजे।

शोभायात्रा निकली

गरबा पंडालो में माताजी की स्थापना हेतु भक्तों द्वारा अपने-अपने स्थान से वाद्ययंत्रो के साथ ट्रैक्टर पर सवार माताजी की शोभायात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा भिन्न-भिन्न स्थानों से ग्राम की प्रमुख गलियों से होते हुए घट स्थापना स्थान पहुंची। पारा बस स्टैंड पर गाँव के पंडित संजय शर्मा द्वारा माता रानी की पूजा अर्चना कर स्थापना की गई। तथा माताजी की महाआरती उतारी गई।

उपहार भेट का आयोजन भी होगा

स्थानीय शनि मंदिर प्रांगण में गांव के राठौर समाज द्वारा ग्राम मे प्रथम वर्ष मंदिर प्रांगण में गरबा नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। वही केसर बाग चौराहे पर स्थित बाल गरबा मंडल द्वारा उपहार योजना का भी आयोजन होगा। उपहार का प्रति प्रसादी कूपन जिसकी राशि पांच सौ रुपया रखी गई।

उप डाकघर से ग्रामीण अंचलों में समय पर नहीं होता है डाक वितरण

माही की गूंज, भामल।

ग्रामीण अंचलों में बने उप डाकघर पर समय पर आने वाले डाक को कर्मचारी समय पर वितरण नहीं कर रहे है। जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। जिसके कारण उप डाकघर में कर्मचारियों की मनमानी व मनमर्जी चल रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार डाकघर को डिजिटल बनाने के साथी कई तरह के महत्वपूर्ण उद्देश्य को सार्थक करने के लिए डाकघर जनसेवा के माध्यम से आम जनता को सब सुविधा मिले इसी उद्देश्य को देखते हुए ग्रामीणों अंचलों के डाकघर को भी डिजिटल किया जा रहा है। वहीं सतत मॉनेढिंग व निगरानी समय पर नहीं होने के कारण ग्रामीण अंचलों में बने उप डाकघर के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। जिससे कहीं न कहीं ग्रामीणों को अपने डाक समय पर नहीं मिल पा रहे हैं।

कुछ ऐसा ही मामला ग्राम भामल में सामने आया, जहां भामल में उप डाकघर पर पदस्थ पूर्व डाक वितरण नाथूसिँह पटेल ने माही की गूंज को जानकारी देते हुए बताया कि, भामल में डाक वितरण की काफी समस्या आ रही है। पूर्व में एक कर्मचारी की पोसि्ंटग हरियाणा से हुई थी। लेकिन उन्होंने भामल डाकघर मे तीन से चार महीने काम किया उसके बाद नौकरी से रिजाइन दे दिया गया। जिसके बाद से ही यहां डाकघर में डाक वितरण करने वाले कर्मचारियों की पोस्ट खाली थी। जिसको देखते हुए पेटलावद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नरेन्द्र कुमावत को अटैचमेंट कर के अतिरिक्त प्रभार दे कर यहां डाक वितरण की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उनके द्वारा दो माह से गांव भामल में डाक वितरण नहीं किया जा रहा है। भामल डाक घर में परवाड़ा भेरूपाड़ा आदि जगह भामल से ही डाक वितरण होते है। लेकिन अतिरिक्त प्रभार होने के बाद भी डाक वितरण नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण यहां के ग्रामीणों को आने वाले नए आधार कार्ड के साथ ही कई तरह की

भामल डाकघर

आवश्यक आने वाली डाक की सामग्री समय पर नहीं मिल पा रही है। जबकी डाकघर पर पदस्थ पूजा बरोड़िया का कहना है, हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भी बता दिया लेकिन उनके द्वारा भी कोई आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताते हैं, जिसको डाक वितरण करने की जिम्मेदारी जिस कर्मचारी को दी गईं उनका नाम नरेन्द्र कुमावत है। वह उनकी मूल पोसि्ंटग मकोडिया है, लेकिन उनको अटैच भामल में कर रखा है। ताकि ग्रामीणों को समय पर डाक वितरण हो पाए इसी उद्देश्य को देखते हुए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जुलाई माह बाद उन्होंने एक भी डाक वितरण नहीं किया ना ही डाक की आने वाली सामग्री व उनकी लिस्ट मुझे नहीं बताई गई।

बारोड़िया मेडम का कहना है, वही स्थानीय ग्रामीण मुझसे आ कर जानकारी लेते है, मैं तो यहां नियमित आ रही हूं। अब अगर समय पर डाक वितरण नहीं हो रहा है। तो मेने मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को कह दिया है, अब जो भी होगा वहीं से होगा। अब यहां सवाल यह उठता है कि, जब अटैचमेंट कर रखा है और जो कर्मचारी नियुक्त कर रखा है वह आखिर डाक किस उद्देश्य से वितरण नहीं कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए इस और ध्यान देना चाहिए तथा समस्या का निदान करना चाहिए।

वही जिस कर्मचारी को अटैचमेंट कर रखा है। उससे माही की गूंज के प्रतिनिधि ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया आपको गलत जानकारी दी गई है। मैं, समय पर डाक वितरण कर रहा हूं। मेरी पोसि्ंटग मकोडिया में है और मुझे वहां भामल में अटैच कर रखा है। जबकि मैं परवाड़ा, भेरूपाड़ा, सभी जगह डाक वितरण कर रहा हूं। अब यहां कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है यह तो वरिष्ठ अधिकारी जांच करें लेकिन कहीं ना कहीं यहां ग्रामीणों को चार माह से समय पर डाक नहीं मिल पाने के कारण परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है।

संपादकीय

नवरात्र की शक्ति

रविवार को हमने अमावस्या पर पितृ-विसर्जन के जरिये हमारे जीवन को समृद्ध करने वाले पुरखों को पुण्य स्मरण कर विदा किया। सोमवार का सूरज नवरात्र की बहुआयामी शक्ति से पूरे देश में आस्था का उल्लास और उमंग भर रहा है। नवरात्र के साथ ही देश में पर्व-त्योहारों की ऐसी श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो जनमानस के तन-मन को ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे जाती है। ऐसे वक्त में जब देश अमेरिका के ट्रैरिफ आतंक से जूझ रहा है, स्वदेशी का मंत्र हमारी आर्थिक व राष्ट्रीय संप्रभुता का संरक्षक बन सकता है। निस्संदेह, दूसरे देशों पर हमारी आर्थिक निर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये विदेशी का मोह, कहीं न कहीं राष्ट्रीय सरोकारों से हमारे विमुख होने का पर्याय भी है। देश में आर्थिक संपन्नता आई तो साथ ही विदेशी वस्तुओं को सम्मोहन भी बढ़ा है। हम स्वदेशी के उस मंत्र को भूल गए, जिसने परतंत्र भारत को आजाद कराने व ब्रिटिश सत्ता की चूलें हिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। नवरात्र का पर्व व्रत और शक्ति की आराधना का पर्व है। ऐसी शक्ति जिससे राष्ट्र, समाज व व्यक्ति का कल्याण हो सके। ऐसे वक्त में जब लगातार भारत विरोधी कदम उठा रही ट्रंप सरकार ने भारतीय प्रतिभाओं पर अंकुश लगाने के लिये एच-1 बी वीजा को अस्त्र बनाया है, हमें अपनी प्रतिभाओं को देश में सहेजने का प्रयास करना चाहिए। देश के नीति-नियंताओं को मंथन करना होगा कि अमेरिका के लिये महकने वाली प्रतिभाएं देश को क्यों नहीं महका सकती?

यह अच्छी बात है कि नवरात्र पर्व की शुरुआत जीएसटी सुधारों के साथ हो रही है। अब तक दैनिक उपभोग की वस्तुओं व दवाओं आदि पर अतार्किक शुल्क लगाया गया था। जिसे बहुत पहले ही सुधार लिया जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर कहा जा सकता है कि अब लोगों की बचत बढ़ेगी। बचत बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार को गति मिलेगी। कुल मिलाकर स्वदेशी अर्थव्यवस्था गतिमान होगी, भारतीय-उद्योग धंधों को संबल मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। निस्संदेह, जीएसटी दरों में कमी और पर्व-त्योहारों के इस मौसम में देश के असंगठित क्षेत्र को शक्ति मिलेगी, जो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत भी है। नवरात्र के व्रत का पहला संकल्प हमारी आस्था और सेहत से है। देश आज मोटापे और उससे उत्पन्न गैर संक्रामक रोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा हृदयाघात से जूझ रहा है। इस नवरात्र के दौरान हम अपने खानपान को संयमित करके आस्था के संबल के साथ अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं। हमारे पर्व-त्योहार गहरे तक हमारे व्यावहारिक जीवन से जुड़े हैं। उनके गहरे निहितार्थों को समझने की जरूरत है। ये पर्व व त्योहार महज कर्मकांड ही नहीं है, इसके व्यक्ति, समाज और अर्थव्यवस्था के लिये गहरे संदेश हैं। इस तरह नवरात्र बेटियों को शक्तिशाली बनाने, लैंगिक भेदभाव खत्म करने और समाज में तनाव-अवसाद दूर करके व्यक्ति और समाज को स्वस्थ बनाने का पर्व है। हमें पर्व के मर्म को समझना है।

ट्रंप की एच-1 बी आपदा को अवसर में बदले भारत

अमेरिका की एच1-बी वीज़ा व्यवस्था से राष्ट्रपति ट्रंप की चिढ़ नई नहीं है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी पद संभालते ही अप्रैल, 1917 में एच-1बी वीज़ा की शर्तें कड़ी करने और संख्या घटाने का फ़रमान जारी कर दिया था। फिर भी, यह शायद ही किसी ने सोचा हो कि एच-1बी वीज़ा पर एक लाख डॉलर या लगभग 88 लाख रुपये की फ़ीस थोप दी जाएगी। इसलिए फ़रमान जारी होते ही एच-1बी वीज़ा धारकों और उनकी कंपनियों में ऐसी अफ़रा-तफ़री मची कि अमेरिका से बाहर छुट्टी पर गए कुछ वीज़ा धारक हज़ारों डॉलर के वापसी के हवाई टिकट ख़रीद बैठे ताकि फ़रमान लागू होने से पहले अमेरिका लौट जाएं।

ट्रंप की प्रेस सचिव कैरलाइन लेविट और प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन के स्पष्टीकरणों के बाद लोग थोड़ा आश्वस्त हुए। स्पष्टीकरण में बताया गया कि एक लाख डॉलर की फ़ीस एच-1बी वीज़ा पर आने वाले पेशेवर की जगह उसे लाने वाली कंपनी को भरनी होगी और वह हर वर्ष की जगह केवल एक बार भरनी होगी। वीज़ा की समय सीमा बढ़वाने और छुट्टियां बिताकर लौटने पर कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की ख़ातिर कुछ विशेष कंपनियों को विशेष परिस्थितियों में छूट भी मिल सकती है। इससे एमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ़्ट और गूगल जैसी उन अमेरिकी कंपनियों को छूट मिलने की संभावना भी बन गई है जो सबसे बड़ी संख्या में एच-1बी वीज़ा प्रतिभाओं को बुला रही हैं। इससे यह संकेत भी मिलता है कि एच-1बी वीज़ा पर यह फ़ीस अमेरिका की प्रतिभाओं के रोज़गार बचाने की जगह व्यापार वार्ताओं में भारत की बांह मरोड़ने के लिए लगाई गई है।

गनीमत इस बात की है कि हर साल जारी किए जाने वाले एच-1बी वीज़ाओं की संख्या नहीं घटाई गई है। लेकिन नियमों को कड़ा करते हुए वीज़ा आवेदन बड़ी संख्या में रद्द किए जाने की पूरी संभावना है। बहरहाल, एक लाख डॉलर की फ़ीस और अधिक आवेदन रद्द होने का सबसे बड़ा असर भारत पर ही पड़ेगा क्योंकि हर साल जारी होने वाले 85 हज़ार एच-1बी वीज़ाओं में से 72 प्रतिशत से अधिक वीज़ा भारतीय पेशेवर और अमेरिकी स्नातकोत्तर डिग्रियों वाले शोध छात्र ही हासिल करते हैं। इनमें से भी 65 हज़ार वीज़ा तो एमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ़्ट मेटा, गूगल, टीसीएस और इन्फ़ोसिस जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बुलाई जाने वाली प्रतिभाओं के लिए हैं जो चाहें तो एक लाख डॉलर की फ़ीस भर सकती हैं या फिर अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने की जगह भारत में रखकर वही काम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर करा सकती हैं।

गंभीर समस्या उनकी है जो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों से स्नातकोत्तर डिग्रियां हासिल करने के बाद अमेरिका में रहकर किसी अमेरिकी कंपनी या संस्था में काम करना, अपना कारोबार खोलना या शोध और विकास का काम करना चाहते हैं। बीस हज़ार एच-1बी वीज़ा इन्हीं प्रतिभाओं के लिए आरक्षित रहते हैं। इनके और इनकी कंपनियों व संस्थाओं के लिए एक लाख डॉलर फ़ीस जुटा पाना बहुत कठिन होगा। भारत समेत दुनियाभर से श्रेष्ठतम प्रतिभाएं पढ़ने-पढ़ाने और शोध करने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में आती हैं। वे यहां नई-नई खोज करती हैं, उनका कारोबारों और जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रयोग करती हैं जिससे अमेरिका के विकास को गति मिलती है।

पूर्व राष्ट्रपति रेगन के शब्दों में, अमेरिका में आपकी पृष्ठभूमि को नहीं, सपनों को महत्व दिया जाता है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि वे हर काम का दाम वसूल करने के फेर में दुनिया भर से अमेरिका आने वाली प्रतिभाओं के सपनों को तो तोड़ ही रहे हैं, अमेरिका की उच्च तकनीक और नवाचार शक्ति के उस स्रोत को भी सुखा रहे हैं जिसने अमेरिका को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महाशक्ति बनाया है।

प्रतिभाएं तैयार करने में बड़ी मात्रा में देशों के संसाधन, श्रम और समय लगता है। उन्हें प्रोत्साहित करने और उनका सदुपयोग करने की जगह उन्हें रोकने के लिए भारी-भरकम फ़ीस थोपने की नीति समझ से परे है। वैसे यही सवाल भारत से भी किया जा सकता है। अपनी जिन प्रतिभाओं के लिए अमेरिका जैसे विकसित देशों के दरवाज़े बंद होने पर भारत में जितनी भावनाएं आहत होती हैं उतनी अपनी प्रतिभाओं के पलायन से क्यों नहीं होतीं? आख़िर हमारी प्रतिभाएं अपने सारे संसाधन, श्रम और बुद्धि अपने समाज और देश को छोड़कर भागने में क्यों लगा रही हैं? क्या यह अपने समाज की कुव्यवस्था के प्रति बढ़ते सामूहिक अविश्वास का प्रदर्शन नहीं है? ट्रंप ने वीज़ा की यह फ़ीस चाहे जिस वजह से थोपी हो पर क्या यह भारत को सोचने और आपदा में अवसर तलाश करने को विवश नहीं करती? भारत ने हमेशा संकट से विवश होकर ही सुधार किए हैं। साठ के दशक में अन्न की कमी और भुखमरी से विवश होकर हरित क्रांति की। 1991 में देश दिवालिया हो जाने पर आर्थिक सुधारों की तरफ़ कदम बढ़ाए। आज ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां विदेशी प्रतिभाओं के ख़िलाफ़ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में माहौल बना रही हैं। इससे सचेत होकर भारतीय कंपनियों और सरकार को अपने देश में नवाचार, शोध और विकास के ऐसे अवसर पैदा करने होंगे जो अमेरिका भागती प्रतिभाओं को थाम सकें।

पिछले कुछ सालों से एमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ़्ट, गूगल और एपल जैसी कंपनियों में जहां एच-1बी वीज़ा प्रतिभाओं की मांग बढ़ी है वहीं भारत की इन्फ़ोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों में घटी है। क्योंकि भारत की कंपनियां अब अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के बीपीओ या व्यावसायिक प्रक्रिया केंद्रों से जीसीसी या वैश्विक क्षमता केंद्रों में बदलती जा रही हैं जहां शोध और विकास, डिज़ाइन, डेटा विश्लेषण और कोडिंग जैसे उच्च तकनीक के काम होते हैं। अगले पांच वर्षों में भारत के जीसीसी केंद्रों के तीन गुना हो जाने की संभावना है।

शिवकांत शर्मा

ट्रंप की वीज़ा फ़ीस भारतीय कंपनियों के साथ अमेरिकी कंपनियों को भी उन कामों के केंद्र भारत में खोलने को विवश करेगी जिनके लिए एच-1बी वीज़ा धारकों को अमेरिका बुलाया जाता है। इससे भारत को एच-1बी वीज़ा धारकों से मिलने वाली विदेशी मुद्रा का नुकसान तो होगा लेकिन निर्माण और रोज़गार बढ़ने से देश की आर्थिकी को लाभ भी होगा। परंतु यह सब केवल आत्मनिर्भरता के नारे लगाने से नहीं होगा। इसके लिए महानगरों और प्रथम श्रेणी के शहरों के बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार करने होंगे, कारोबारी प्रक्रिया सरल बनानी होगी और शोध, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा संस्थानों को उद्योगों से जोड़ना होगा।

ट्रंप के उच्च तकनीक वाली चिपों के बैन ने चीन को अपने एआई चिप निर्माण को बढ़ावा देने पर विवश किया और उसने कुछ ही महीनों में अमेरिका जैसी शक्तिशाली चिपों का निर्माण कर दिखाया। एच-1बी वीज़ा फ़ीस थोपने पर भारत की सबसे सटीक प्रतिक्रिया यही होगी कि जो काम कराने के लिए कंपनियां प्रतिभाओं को एच-1बी वीज़ा पर अमेरिका ले जाती थीं वे सारे काम भारत में ही होने लगें।

विज्ञान, आस्था और न्याय में संतुलन की तार्किकता

दवा, दुआ और अदालत का संबंध मानव जीवन के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता हैकृविज्ञान, आस्था और न्याय। ये तीनों अलग-अलग लग सकते हैं, पर असल में एक-दूसरे के पूरक हैं। दवा विज्ञान और तर्क पर आधारित है, दुआ आस्था और मन की शक्ति पर, जबकि अदालत कानूनों और नियमों पर चलती है। अदालत ही वह संवैधानिक ढांचा है जो दवा और दुआ दोनों को अंधविश्वासों और गलत इस्तेमाल से बचाकर संतुलन बनाए रखती है।

अदालत की मुख्य भूमिका चिकित्सा लापरवाही के मामलों में दिखती है, जहां यह सुनिश्चित करती है कि डॉक्टर ने अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाया या नहीं। इसके लिए अदालत 'बोलम परीक्षण' जैसे सिद्धांतों का उपयोग करती है, जो यह तय करते हैं कि डॉक्टर ने उचित सावधानी बरती या नहीं। दूसरे शब्दों में, डॉक्टर को तब तक लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसने ऐसा कुछ किया जो उस समय चिकित्सा क्षेत्र में स्वीकार्य अभ्यास नहीं था। यह प्रणाली डॉक्टरों को बेवजह के मुकदमों से बचाती है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि मरीजों के अधिकार सुरक्षित रहें और चिकित्सा मानकों का पालन हो। अदालत इन तीनों के बीच एक सेतु का काम करती है।

भारत में, न्यायपालिका ने चिकित्सा देखभाल को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना हर नागरिक का 'जीने का मौलिक अधिकार' है। इसका मतलब है कि कोई भी अस्पताल, चाहे वह सरकारी हो या निजी, किसी भी गंभीर मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता, भले ही उसके पास पैसे न हों। यदि कोई अस्पताल ऐसा करता है, तो इसे 'सेवा में कमी' मानते हुए उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत की जा सकती है। इस प्रकार, अदालत केवल न्याय नहीं करती, बल्कि वह चिकित्सा देखभाल के न्यूनतम मानकों को भी स्थापित करती है।

भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्थाएं, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब धार्मिक विश्वास जीवन को खतरे में डालते हैं। यदि कोई वयस्क धार्मिक सोच आधारित उपचार से इनकार करता है, तो यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला हो सकता है, लेकिन जब यह किसी नाबालिग के जीवन से जुड़ा होता है, तो अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। ऐसे मामलों में, अदालत 'जीवन के अधिकार' (आर्टिकल 21) को माता-पिता की धार्मिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण मानती है, यह स्पष्ट करते हुए कि किसी भी धार्मिक विश्वास को मानव जीवन पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसी तरह, इच्छामृत्यु का मुद्दा भी धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोणों के बीच टकराव का एक उदाहरण है। भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है। धार्मिक कारण अक्सर इसे 'ईश्वर के खिलाफ जाने' समान मानते हैं। लेकिन अरुणा शानबाग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'मृत्यु की प्रक्रिया में गरिमा' को 'जीवन के अधिकार' का एक हिस्सा माना। यह फैसला दर्शाता है कि अदालत धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं को ध्यान में रखती है, लेकिन अंतिम निर्णय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और गरिमा पर आधारित होता है।

सोजन बनाम केरल राज्य (2018) का मामला इस बात का एक कड़वा सबक है कि जब आस्था अंधविश्वास बन जाती है, तो वह जीवन को खतरे में डाल सकती है। एक पिता ने अपनी बेटी का मेडिकल इलाज बंद करवाकर उसका धार्मिक इलाज शुरू करवाया, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने धार्मिक विश्वास के नाम पर की गई इस लापरवाही को दंडनीय अपराध माना और पिता को सजा दी। यह मामला स्पष्ट करता है कि सच्ची आस्था कभी जीवन-विरोधी नहीं हो सकती। यदि कोई विश्वास, वैज्ञानिक प्रमाणों के खिलाफ जाकर, किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालता है, तो वह लापरवाही है, और कानून उसे दंडित करेगा। यह हमें सिखाता है कि कानून, नैतिकता और विज्ञान के मानकों से ऊपर कोई विश्वास नहीं है, और इन मानकों को बनाए रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

शर्ली थॉमस बनाम केरल राज्य (2022) का मामला एक ऐतिहासिक उदाहरण है जो दवाएं, दुआ और अदालत के बीच के नाजुक संबंध को दर्शाता है। इस मामले में, एक महिला ने अपनी लाइलाज बीमारी के कारण इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मौलिक है, लेकिन जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा विज्ञान इलाज का आधार है, जबकि आस्था और दुआएं व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और उम्मीद का स्रोत हैं। इस फैसले ने यह स्थापित किया कि अदालत का काम केवल कानून लागू करना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा को भी सुनिश्चित करना है। यह मामला दिखाता है कि जब विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं तो आस्था उम्मीद दे सकती है, लेकिन इन्हें एक-दूसरे का विकल्प नहीं, बल्कि एक-दूसरे का पूरक माना जाना चाहिए।

डॉ. सुधीर कुमार

दवाएं, दुआ और अदालत एक त्रिवेणी के तीन संगम हैं, जहां प्रत्येक का अपना महत्व है। दवा आधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रतीक है, दुआ मानव मन की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और अदालत वह बाड़ है जो इस प्रणाली को सुरक्षित रखती है। समाज की प्रगति के लिए इन तीनों के बीच संतुलन अनिवार्य है। हमें दवा की शक्ति को स्वीकार करना चाहिए, दुआ की क्षमता को समझना चाहिए और अदालत के न्याय का सम्मान करना चाहिए।

एक स्वस्थ, नैतिक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम इन तीनों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखें। हमें यह समझना होगा कि सच्ची आस्था वैज्ञानिक ज्ञान की विरोधी नहीं है, बल्कि उसका पूरक हो सकती है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, 'धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है'। यह उद्धरण इन तीनों के बीच के संबंधों को सटीक रूप से परिभाषित करता है।

पंजाब को बाढ़ से बचाने को बने कारगर रणनीति

पंजाब ने 1988 के बाद पांचवीं बार विनाशकारी बाढ़ का सामना किया है। इससे पहले, राज्य में 1993, 2008, 2019 और 2023 में विनाशकारी बाढ़ आई थी। संयोगवश, इन बाढ़ों के लिए केवल सतलुज और व्यास नदियां ही ज़िम्मेदार रही हैं। रावी नदी केवल इस साल ही रौद्र रही। बाढ़ का पैटर्न कमोबेश हर बार जाना-पहचाना होता है। इस साल, अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले दो सप्ताहों में सतलुज और व्यास के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश हुई, जबकि दोनों नदियों पर बने बांधों के जलाशय पहले ही अधिकतम भंडारण स्तर तक भर चुके थे। परिणामस्वरूप, जलाशयों को सुरक्षित और इष्टतम स्तर पर बनाए रखने के लिए स्पिल-वे से प्रचुर मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा, जो पूरे वेग से निकला। इस निकासी के साथ-साथ, दोनों बांधों के निचले उप-पहाड़ी इलाकों से उत्पन्न भारी वर्षा जल प्रवाह ने भी दोनों नदियों को उफान पर ला दिया, जिससे राह में पड़ने वाले कमज़ोर तटबंध टूट गए और बड़ी संख्या में गांवों के खेत जलमग्न हो गए।

इस बार, तीनों नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों की तुलना में उप-पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण विनाशकारी बाढ़ आई और बांधों के निचले इलाकों में लाखों क्यूसेक पानी पैदा होकर प्रवाहित हुआ। उदाहरणार्थ, 7 सितंबर तक, बीबीएमबी ने केवल सीमित मात्रा में पानी छोड़ा, जो बिजली संयंत्रों को उनकी निर्धारित क्षमता पर चलाने के लिए आवश्यक था। सतलुज और ब्यास नदियों में पानी की आमद लगभग पूरी तरह से बांधों से निचले इलाके की सहायक नदियों एवं अन्य धाराओं द्वारा लाए गए प्रचुर जल-प्रवाह के कारण थी। उदाहरण के लिए, स्वां और सिरसा नामक दो बड़ी सहायक नदियों सहित अन्य 16 धाराएं हैं, जो नंगल बांध और रोपड़ हेडवर्क्स के बीच के इलाके में सतलुज में आन मिलती हैं। इन 16 धाराओं का संयुक्त प्रवाह 3.0 लाख क्यूसेक से अधिक रहा।

रावी नदी के मामले में प्रवाह का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है। यहां, बीबीएमबी के विपरीत, पंजाब के सिंचाई विभाग ने रणजीत सागर जलाशय के आंतरिक प्रवाह और बाह्य प्रवाह के आंकड़े मीडिया को नहीं बताए हैं। ऐसी संभावना है कि स्पिल-वे से 600 मेगावाट बिजली संयंत्र चलाने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पानी छोड़ा गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि रणजीत सागर जलाशय की वर्तमान भंडारण क्षमता केवल 2.33 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जोकि पौंग बांध जलाशय के 30 प्रतिशत और भाखड़ा जलाशय के 38 प्रतिशत जितनी है। इसके अलावा, रणजीत सागर, पौंग बांध और भाखड़ा बांध जलाशयों का क्षेत्रफल क्रमशः 52, 241 और 168 वर्ग किलोमीटर है। यह तुलना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जलाशय के छोटे आकार के कारण रणजीत सागर बांध विराट मात्रा में आए पानी को संभालने में असमर्थ है और स्पष्टतः अधिकतम प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकता। रावी नदी से लगभग 4.0 लाख क्यूसेक अभूतपूर्व प्रवाह का यह एक और कारण हो सकता है।

फिर, डलहौजी के पास रावी नदी के ऊपर की ओर, 121 मीटर ऊंचा चिमेरा बांध है और इसका कुल संग्रहण क्षेत्र लगभग 0.45 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है। इसी प्रकार, भाखड़ा बांध के ऊपर की ओर 167 मीटर ऊंचा कोल बांध का संग्रहण क्षेत्र 0.6 अरब घन मीटर में है। दुर्भाग्य से, इन दोनों बांधों को नदी-प्रवाह (रन ऑफ द रिवर) परियोजनाओं के रूप में डिज़ाइन किया गया है। अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, इनके जलाशयों को वर्ष भर ऊपर तक भरा रखा जाता है। यदि इन दोनों बांधों को भी संग्रहण बांधों के रूप में डिज़ाइन किया गया होता, तो इनके जलाशय आपातकालीन अवधियों के दौरान बड़े आने वाले जल प्रवाह को अपने अंदर समाहित रणजीत सागर तथा भाखड़ा बांधों के स्पिल-वे पर चरम प्रवाह के बोझ को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते थे।

पंजाब के आठ जिलों के 2000 गांवों में बाढ़ के भयावह स्तर और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की व्यापक क्षति को देखते हुए, पंजाब और केंद्र सरकार, दोनों को तत्काल निवारक उपाय करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की भयावह बाढ़ की स्थिति फिर कभी न बने। ये उपाय अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों होने चाहिए, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

अल्पकालिक उपाय के रूप में भारतीय मौसम विभाग द्वारा वर्षा के पूर्वानुमान सही निकलते पाए जाने पर, बीबीएमबी को 20 अगस्त के आसपास दोनों बांधों में जलाशय स्तर को पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) से कम-से-कम एक मीटर नीचे रखना चाहिए ताकि अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में अधिक जल प्रवाह को समायोजित किया जा सके। रणजीत सागर बांध के इंजीनियरिंग विंग भी ऐसी नीति अपनाए। दूसरा, सभी पुलों के नीचे के जलमार्गों से जमा हुई तमाम गाद को पूरी तरह से साफ़ किया जाए। इसी प्रकार, वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले सभी वेयर्स और बैराजों के गेटों की कार्यक्षमता की जांच हो। कीचड़ व मलबे के कारण माधोपुर हेडवर्क्स के केवल पांच गेट ही खोले जा सकें।

तीसरा, सिंचाई विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि तीनों नदियां सुरक्षित तरीके से 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए विभाग मौजूदा कमजोर तटबंधों को मज़बूत करे, खनन ठेकेदारों द्वारा तटबंधों पर लगाई सेंधों को बंद करे, पूरक तटबंध बनाए, नदियों के पूरे रास्ते भर तटबंधों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पर और ग्रोइन बनाए जाएं जो अगली बरसात से पूरा हो जाना चाहिए। इसी तरह, सतलुज नदी के हरिके और हुसैनीवाला बैराज के बीच के 53 किलोमीटर के हिस्से में नदी प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि एकीकृत हुई नदी, सतलुज और ब्यास के संयुक्त प्रवाह को सुरक्षित रूप से संभाल पाए।

दीर्घकालिक उपाय के रूप में पंजाब सरकार को चाहिए कि रिकांगपिओ के ऊपरी हिस्से में सतलुज नदी पर खाब परियोजना को पुनर्जीवित करके 1.0 बीसीएम क्षमता का एक भंडारण बांध बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करे। इस बांध का भंडारण अचानक आने वाली बाढ़ को अपने में समा कर, भाखड़ा जलाशय तक मार करने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने में मददगार होगा। इसके अलावा, यह सतलुज नदी के निचले हिस्से में बने सभी जलविद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी बहुत सहायक होगा।

आरएन मलिक

दूसरे, ब्यास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में इस प्रकार का भंडारण बांध बनाने की संभावना सीमित है। लेकिन कुछ कम ऊंचाई के गाद-संग्रहण बांध अवश्य बनाए जाने चाहिए क्योंकि पंडोह और पौंग बांधों में गाद चिंताजनक स्तर तक जमा हुई है।

तीसरे, रावी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कुछ सहायक नदियों पर भंडारण बांध बनाने की संभावना है। यह घाटी दामोदर नदी घाटी निगम द्वारा उठाए गए कदमों की तर्ज पर अतिरिक्त जल संसाधन विकसित करने और बाढ़ रोकथाम उपाय करने के लिए एक उपयुक्त विकल्प है, जहां पश्चिम बंगाल के हुगली, बर्धवान और हावड़ा जिलों में विनाशकारी बाढ़ को रोकने हेतु दामोदर नदी और इसकी दो प्रमुख सहायक नदियों पर चार बांध बनाए गए थे। वर्तमान में, रणजीत सागर बांध अपने छोटे जलाशय के कारण बड़े पैमाने के प्रवाह को संभालने में असमर्थ है।

तीनों बांधों के निचले उप-पहाड़ी क्षेत्रों में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए एक युद्धस्तरीय कार्यक्रम शुरू हो, विशेष रूप से स्वां, सिरसा, चक्की, काली बेईं, उझ और सिसवां जैसी सहायक नदियों को नियंत्रित करने के लिए। इनमें से कुछ सहायक नदियों में कभी-कभी तो 70000 क्यूसेक जितना पानी बहता है। इनसे पंजाब में विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति को हमेशा के लिए रोका जा सकता है।

कलेक्टर को हटानी पड़ी सोशल मीडिया से पोस्ट

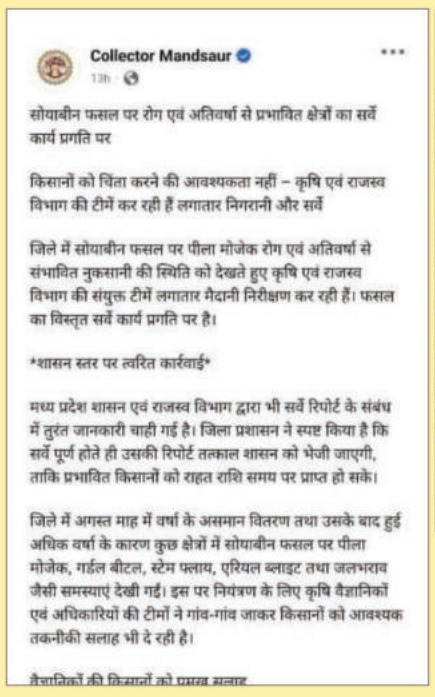

माही की गूंज, मंदसौर।

सोयाबीन फसल इस साल पीला मोजेक वायरस की भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद खेतों में पहुंचकर किसानों से इसकी जानकारी ली। किसान बर्बाद सोयाबीन का मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मंदसौर कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट की, इससे किसानों में नाराजगी है। हालांकि किसानों में नाराजगी और लगातार विरोध में आ रहे कमेंट्स को देखते हुए इस पोस्ट को हटा लिया है, लेकिन अब स्क्रीन शॉट काफी वायरल हो रहा है।

वायरल पोस्ट में क्या लिखा हुआ है

जो स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है वो मंदसौर कलेक्टर के सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक का है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि सोयाबीन की फसल पीले मौजक से पूर्णतया नष्ट होने की खबर भ्रामक है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं।

कृषि विभाग की टीम निगरानी कर रही है। इस पोस्ट के बाद मंदसौर के किसानों में भारी गुस्सा है। वहीं किसान इस पोस्ट को लेकर विरोध जता रहे हैं।

इस पोस्ट पर विरोध के स्वर उठते ही पोस्ट हटा ली गई और थोड़ी देर में नई पोस्ट डाली गई, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी सर्वे करते हुए दिखाइए दे रहे हैं। हालांकि माही की गूंज वायरल स्क्रीन शॉट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

पोस्ट डिलीट करने के बाद मंदसौर कलेक्टर की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया। जिसमें कहा गया कि सोयाबीन फसल पर रोग व अतिवर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कार्य प्रगति पर है। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं- कृषि व राजस्व विभाग की टीमें लगातार निगरानी और सर्वे कर रही हैं।

अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सोयाबीन की फसल के नष्ट होने की खबर को भ्रामक बताने वाली जानकारी किस जिम्मेदार अधिकारी ने डीएम को दी। यदि वो जिले की मुखिया को भ्रामक जानकारी देने से नहीं चूक रहे है तो किसानों के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे? यह सहज ही समझा जा सकता है।

क्या है हालात

अतिवृष्टि और पीले मोजेक की वजह से जिले के अधिकतर किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर पकी फसल की पैदावार काफी कम बैठ रही है। आकलन से निराश किसानों ने जिले में कुछ जगह अपनी फसल को रोटो वेटर से नष्ट किया है। वहीं एक किसान ने कटाई के बाद अपनी फसल में आग लगा दी, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो हुआ।

पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे, प्रशासन ने लिए बड़े फैसले

माही की गूंज, मंदसौर।

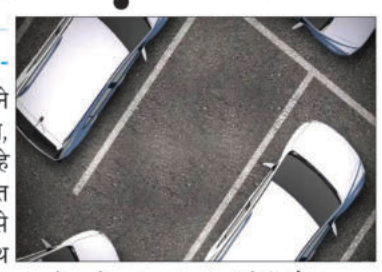

कलेक्टर अदिति गर्ग ने कहा कि प्रतापगढ़ पुलिया, घंटाघर और बीपीएल चौराहे में पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे, जिससे यातायात सुगम होगा। साथ ही किसी भी क्षेत्र के अंदर वाहन खड़े करने पर सख्त कार्रवाई होगी और चालान काटा जाएगा।

बीपीएल चौराहे की रोटरी को छोटा करने का निर्देश कलेक्टर द्वारा दिया गया है। कलेक्टर का कहना है कि इससे यातायात सही चलेगा और जाम नहीं लगेगा। घंटाघर मंडी में तत्काल टू व्हीलर पार्किंग व्यवस्था को भी आरंभ करने का कलेक्टर ने आदेश दिया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि, 8 लेन सड़क पर हर 500 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले के ब्लैक स्पॉट का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद उन पर उपाय किए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो। साथ ही सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों पर चालान किया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। किसी भी अस्थाई निर्माण की अनुमति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

कई स्थानों पर टू व्हीलर पार्किंग व्यवस्था शुरू की जाएगी

यातायात को सुगम बनाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग द्वारा कई निर्णय लिए गए, जिसमें घंटाघर मंडी में तत्काल टू व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था शुरू करने की पहल सबसे पहले होगी। प्रतापगढ़ पुलिया, घंटाघर और बीपीएल चौराहे पर पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे, जिससे शहर में जाम कम लगेगा। यदि निर्धारित क्षेत्र के बाहर वाहन खड़े पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी और चालान काटा जाएगा।

कई बड़े अधिकारी शामिल रहे

जिले में यातायात सुधार और दुर्घटना कमी को लेकर हुई इस बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल रहे। इनमें एसपी विनोद कुमार मीणा, एडिशनल एसपी तेज सिंह बघेल, नगर पालिका अध्यक्ष रामादेवी बंशीलाल गुर्जर, एसडीएम पीडी, परिवहन विभाग सहित संबंधित विभागों के कई अधिकारी शामिल रहे।

महिला सुरक्षा के लिए रतलाम पुलिस ने शुरू किया 'मैं हूं अभिमन्यु अभियान'

माही की गूंज, रतलाम।

महिला सुरक्षा के लिए रतलाम पुलिस ने 'मैं हूं अभिमन्यु अभियान' की शुरुआत की है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य समाज में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है। अश्लीलता, भ्रूण हत्या, लिंग भेद जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए जागरूक करना है। बता दें, यह अभियान 10 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के तहत रतलाम पुलिस पुरुषों और बालकों को महिलाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार करने के लिए जागरूक और प्रेरित करेगी।

यह अभियान 10 दिवसीय होगा। इसी दौरान एसपी ने युवाओं से कहा कि वे अभिमन्यु की तरह महिला और बालिका की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं और आगे आएं तथा उन पर होने वाले अत्याचार को कम करें।

कौन संभालेगा बागडोर

इस अभियान की भागदौड़ संभालेंगी थाना प्रभारी रेखा चौधरी और आजाद पार्वती गॉड। पूरी टीम की देखरेख करेगी। इसी दौरान टीम विभिन्न कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, गरबा पंडालों और दुर्गा पूजा स्थलों पर जाकर अनेक कार्यक्रम करेगी, जिनमें भाषण, चित्रकला, संगोष्ठी, युवा संवाद आदि जैसे विषय शामिल होंगे। इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान एसपी अमित कुमार ने बताया कि यह अभियान पुलिस मुख्यालय भोपाल की पहल है, जिसका नाम 'मैं हूं अभिमन्यु' है। यह अभियान महिला सुरक्षा आईपीएस अनिल कुमार की देखरेख में चलाया जाएगा।

क्यों जरूरी है महिलाओं के प्रति जागरूकता

जब समाज में महिलाओं को समान अधिकार और समान अवसर मिलते हैं, तभी वास्तविक प्रगति संभव है। एक देश के लिए महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूकता से उनके साथ होने वाले शोषण, भेदभाव और हिंसा को कम किया जा सकता है। साथ ही, महिला के प्रति जागरूकता समाज के संतुलित विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

प्राइवेट क्लीनिकों का निरीक्षण, तीन अस्पताल संचालकों को चेतावनी पत्र जारी

माही की गूंज, रतलाम।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संध्या बेलसरे ने बताया कि नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत रतलाम जिले में क्लीनिक नर्सिंग होम अस्पताल आदि के संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। राम मंदिर चौराहा गुजरात स्वीट्स के पास क्लासिक डेंटल क्लीनिक में बीडीएस डॉ जयेश सांखला और बीडीएस डॉ स्वप्निल सांखला द्वारा डेंटल क्लिनिक का संचालन किया जाना पाया गया। किंतु उनके पास नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप जीवित पंजीयन नहीं होना पाया गया इस क्रम में दोनों चिकित्सकों को नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन करने हेतु चेतावनी पत्र जारी किया गया।

रतलाम शहरी क्षेत्र में डॉ. सत्यनारायण पडियार द्वारा क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। क्लीनिक में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की दवाइयां के साथ कुछ एलोपैथिक दवाइयां भी पाई गई। निरीक्षण के दौरान क्लीनिक पर किसी भी मरीज का उपचार नहीं किया जा रहा था। नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा का पंजीयन किया जाना प्रावधानित नहीं है।

इस क्रम में संबंधित चिकित्सक को एलोपैथिक दवाइयां ना रखने के लिए चेतावनी पत्र जारी किया गया है। जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा लोकेंद्र टॉकीज चौराहा आइसीआइसीआइ बैंक के सामने साइ डेंटल क्लिनिक का संचालन किया जाना पाया गया।

इस क्लीनिक में डॉक्टर अतीक जाधव बी डी एस चिकित्सक द्वारा डेंटल क्लिनिक का संचालन किया जाना पाया गया किंतु नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप जीवित पंजीयन नहीं पाया गया। अतः संबंधित को जिला कार्यालय में नर्सिंग एक्ट के अनुरूप पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु चेतावनी पत्र जारी किया गया। निरीक्षण में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश मंडलोई , जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी आशीष चौरसिया, सहायक कर्मचारी श्रीमती शीला चौहान आदि उपस्थित रहे।

सोयाबीन फसल की खरीद हेंतु समर्थन मूल्य पर पंजीयन शीघ्र प्रारंभ करने की मांग

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के विधायक विपिन जैन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सोयाबीन की फसल की खरीद हेतु समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पंजीयन शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। विधायक जैन ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से कहा कि, वर्तमान समय में सोयाबीन की कटाई प्रारंभ हो चुकी है, किंतु पिला मोजेक, अतिवृष्टि और अफलन के कारण सोयाबीन का उत्पादन औसत से भी बहुत कम हुआ है तथा अब तक समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ नही की गई है। फलस्वरूप प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव 4 हजार प्रति क्विंटल से भी कम दर पर बिक रहा है। जैन ने कहा कि फसलों की खरीद हेतु केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके और उन्हें नुकसान ना उठाना पडे। वर्तमान वर्ष हेतु सोयाबीन का (एमएसपी) 5328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। किंतु समय पर पंजीयन एवं खरीद प्रक्रिया प्रारंभ न होने के कारण प्रदेश के किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 1300 से 1500 रुपये तक का सीधा नुकसान हो रहा हैं।

विधायक जैन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र अतिशीघ्र समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद हेतु पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ करवाने की कृपा करें ताकि किसान अपनी उपज का वाजिब मूल्य प्राप्त कर सकें और उन्हे आर्थिक क्षति का सामना न करना पडे। उपरोक्तानुसार आगामी कार्यवाही से प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा उनकी आजीविका सुरक्षित रह सकेगी।

पहाड़ी पर विराजित देव डूगंरी माता के दर्शन के लिए भक्त 151 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं मंदिर

माही की गूंज, मंदसौर।

प्राकृतिक सौंदर्य में विराजमान प्राचीन माता देवडूंगरी मन्दिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के प्राचीनतम मन्दिरों में से एक है। यह मंदिर मुख्यालय से दूर रेवास-देवडा मार्ग पर एक पहाड़ी पर लगभग 9 कि.मी दूरी पर स्थित है। माता देवडुंगरी पहाड़ी पर लगभग 151 सीढ़ियां ऊपर चढ़ कर मंदिर मे माता के दर्शन के लिए आना होता है। इस देवडूंगरी माता मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना बताया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में स्थापित मंदिर का उल्लेख भाट समाज की पोथी में भी पाया गया है। प्रति रविवार को यहां चौकी भी लगती है।

घरौंदे बनाने का है महत्व, सन्तान प्राप्ति की मनोकामना भी होती है पूर्ण

देव डूगंरी माता मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना माता पूरी करती हैं। जिनके स्वयं का मकान नहीं होता है ऐसे भक्त यहां पर सच्चे मन से छोटे-छोटे पत्थरों से घर बनाते है, माता को याद करते है, जिस पर माता उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। वहीं सन्तान प्राप्ति के लिए शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहां प्रति रविवार को 10.30 बजे महाआरती होती है। देव डूगंरी माता भक्त मंडल के राधेश्याम मारू व ट्रस्ट कोषाध्यक्ष बंशीलाल राठौर ने बताया कि यह मंदिर तेली समाज का है। इसका उल्लेख भाट समाज की चारण पोथी में भी है। माता के मंदिर का जीर्णोद्धार पिछले 7 साल से चल रहा है। देवडूंगरी माताजी 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजित माता है।

घट स्थापना के साथ ही नौ दिनों तक होते है आयोजन

नवरात्रि पर्व के नौ दिवसीय आयोजन मे वाड़ी व घट स्थापना, कन्या पुजन, वाड़ी विसर्जन (खप्पर यात्रा) व 9 दिवसीय कथा, प्रसादी वितरण होगा। नवरात्रि में 22 सितंबर सोमवार से नियमित 9 दिवस तक महाआरती प्रातः 10.30 बजे होगी। 28 सितंबर तक नियमित श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन हो रहा। पं. प्रियाशराज व्यास भटपचलाना वाले के श्रीमुख द्वारा यहां दूसरी बार कथा वाचन किया जा रहा है। वे पिछले 9 साल से यहां माता रानी की सेवा में लगे हैं।

मंदिर के नीचे परिसर में विकसित हो रहा है वन क्षेत्र

माताजी के मंदिर के नीचे तलहटी पर वन विभाग मंदसौर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक बडे क्षेत्र में वन क्षेत्र बनाया जा रहा है जहां विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाये जा रहे है और झूले चकरियों के साथ फूड जोन भी बनाया जा रहा है।

कब्र खोदने वाला दो बच्चों का हत्यारा गिरफ्तार

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा के बड़े कब्रिस्तान में कब्रें खोदकर शवों के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंचा। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह तांत्रिक क्रिया के लिए शवों के बाल काटता था।

बीबीपुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया है और अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पहले अपनी दो बच्चों की हत्या कर चुका है।

यह भी बताया गया कि 21 सितंबर, रविवार को बड़े कब्रिस्तान में दो कब्रें खुली मिली थीं। इनमें से एक महिला की कब्र थी। परिजनों ने बताया कि शव के पास छेड़छाड़ हुई थी और शव के पास के कपड़े उलटे पड़े थे। इससे पहले 19 मई को बड़े कब्रिस्तान और सिहाड़ा कब्रिस्तान में छह कब्रों के साथ इसी तरह की घटनाएं हो चुकी थीं।

पुलिस ने कब्रिस्तान में 13 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। 21 सितंबर के फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध युवक नजर आया। आरोपी की पहचान अय्यूब खान (50), निवासी ग्राम मुंदवाड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने उसे मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया।

आरोपी ने अपनी पहली संतान को जलाकर मार डाला था। 2011 में उसने दूसरी संतान को पानी में डुबाकर हत्या की थी। तीसरी संतान की हत्या में उसे उम्र कैद हुई थी। 5 मई 2025 को वह केंद्रीय जेल से रिहा हुआ। जेल से छूटने के केवल पांच दिन बाद, यानी 19 मई को उसने फिर से कब्रिस्तान में छेड़छाड़ की। आरोपी अमावस्या का दिन चुनता था, ताकि कोई उसे पकड़ न सके।

पुलिस पूछताछ में अय्यूब ने बताया कि उसने जेल में रहते तांत्रिक क्रिया सीखी थी। एक कैदी ने उसे समझाया था कि कब्र से शवों के बाल काटकर उन पर क्रिया करने से शक्ति मिलती है। रिहा होने के बाद उसने इसी कारण कब्रें खोदना शुरू किया।

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी निर्वस्त्र नजर आया था। परिवार वालों को आशंका थी कि उसने शवों के साथ दरिंदगी की है। आरोपी ने पूछताछ में इस बात का जिक्र किया, लेकिन इसे साबित करने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराना पड़ता, जिसके लिए न परिजन तैयार हुए और न समाज। इसलिए पुलिस ने मामला तांत्रिक क्रिया से जोड़ा।

एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि अय्यूब पर हत्या, चोरी और दहेज प्रताड़ना समेत कुल 13 मामले दर्ज हैं। इसी आधार पर उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर है।

यूपी का आरोपी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन जिले की महाराष्ट्र सीमा के से लगे क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास कुल 1,000 रुपए कीमत के दो देसी पिस्टल और एक कट्टा जब्त किए गए। फिलहाल आरोपी से हथियारों की खरीद और नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

थाना चैनपुर अंतर्गत गेहलोद सेमलिया क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक सिंगनूर से अवैध हथियार खरीदकर लौट रहा है और आमडी फाटे पर बस का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर हेलापड़ावा चौकी प्रभारी एसआई रमेश गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास दो देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवम सुनील अवस्थी, निवासी रायबरेली (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसने सिंगनूर से ये हथियार खरीदे थे। पुलिस को शक है कि आरोपी किसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसने ये हथियार कहां और किससे खरीदे तथा किस उद्देश्य के लिए लाए थे।

सोलर प्लांट कंपनी पर जमीन हड़पने का आरोप

माही की गूंज, खंडवा।

एक किसान ने मसाया सोलर एनर्जी कंपनी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। किसान ने बताया कि कंपनी ने सामान रखने के लिए 2020 में उससे एक एकड़ जमीन ली थी। खेत में 6 हजार फलदार पेड़ लगे थे। बदले में दो साल के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपये का मुआवजा और किराया दिया गया। लेकिन पिछले दो साल से किराया तक नहीं दिया जा रहा है।

किसान का कहना है कि दलाल और कुछ राजनीतिक नेताओं ने जमीन का खसरा बदलकर सुधारने का लालच देकर उससे 12 लाख रुपये ठग लिए।

भूमिकामी सुशील तिवारी ने बताया कि उन्हें भाजपा नेता श्याम पाटीदार और आजम गौरी मसाया सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत व्यक्ति के रूप में मिलने आए थे। इन्होंने 19 महीने के लिए जमीन किराए पर लेने की बात कही और प्रतिमाह किराया 1 लाख 40 हजार रुपये तय किया। कहा गया कि 19 महीने बाद जमीन खाली करनी होगी या किराया देकर आगे भी जमीन रख सकते हैं।

किसान ने साफ किया था कि जमीन मंदिरों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगी और पूजा-पाठ में कोई रोक नहीं होगी। लेकिन किराया देने के बाद भी आजम गौरी और श्याम पाटीदार ने जमीन पर कब्जा कर लिया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

किसान ने बताया कि उनके 6 हजार फलदार पेड़, जिसमें आम, जामुन, संतरा, अनार, आंवला, नींबू आदि शामिल थे, काट दिए गए। साथ ही सागवान और चंदन के पेड़ भी नष्ट किए गए। टीन शेड, तार फेंसिंग, गौशाला, पक्के कुएं की दीवारें और मंदिर का आरसीसी का ओटला भी तोड़ दिया गया।

सुशील तिवारी ने यह भी कहा कि जमीन के

खसरे सुधार कर उन्हें ऊँचे रेट में बेचने का लालच दिया गया। इसके लिए उनसे 12 लाख रुपये लिए गए और कहा गया कि यह पैसे एसडीएम को देने हैं।

बीजेपी नेता श्याम पाटीदार का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदी है और भुगतान पूरा कर दिया गया है। सौदा कानूनी रूप से सही है और मामला आजम गौरी का है।

40 से अधिक परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी जिले के ग्राम तलून खुर्द में नायब तहसीलदार द्वारा 40 से अधिक परिवारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। इसके विरोध में भीलीस्थान लायन सेना के नेतृत्व में पीड़ित परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कार्यालय का मुख्य द्वार बंद होने पर सभी लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए।

भीलीस्थान लायन सेना के नगर अध्यक्ष राकेश मंडलोई ने बताया कि ये आदिवासी, मानकर और धनगर समाज के गरीब परिवार हैं। ये सभी पिछले कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। इन परिवारों के पास रहने के लिए कोई दूसरा घर या जमीन नहीं है। सभी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं।

कई परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है। सरपंच प्रतिनिधि लोकेश नरगावे के अनुसार, सरकारी लापरवाही और निरक्षरता के कारण परिवार भू-अधिकार पट्टों से वंचित रह गए हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बड़वानी नगर में मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण, अवैध कालोनियां और बड़े गोदाम बने हुए हैं। उनकी मांग है कि पहले उन पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के माध्यम से अतिक्रमण नोटिस रद्द करने और भू-अधिकार पट्टे देने की मांग की गई है।

पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं और उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। यदि हमारे घर तोड़े जाते हैं तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम परिवार सहित जिला कलेक्टर परिसर में स्थायी धरना देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन बड़वानी की होगी।

एनएसएस का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया

माही की गूंज, खरगोन।

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का 56वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व स्वयंसेवक मिलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 200 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की खास बात रही निमाड़ का पारंपरिक गणगौर नृत्य और आदिवासी भगोरिया नृत्य, जिन्हें स्वयंसेवकों ने जीवंत प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। मंच पर पूर्व एवं वर्तमान स्वयंसेवकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष दीपक कानूनगो और प्राचार्य डॉ. जी.एस. ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय सेवा योजना को युवाओं के व्यक्तित्व विकास और सामाजिक चेतना का एक मजबूत मंच बताया। उन्होंने कहा कि एनएसएस छात्रों को समाज सेवा के साथ-साथ नेतृत्व, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की सीख देता है।

कार्यक्रम में जिला संगठक अधिकारी सुरेश अवासे ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पूर्व स्वयंसेवकों के योगदान को सम्मानित करना और उनके अनुभव वर्तमान युवाओं के साथ साझा करना है।

पूर्व स्वयंसेवक तिलोकचंद वर्मा ने कहा, आज साथी स्वयंसेवकों के आने से पुराने शिविरों और गतिविधियों की यादें ताजा हो गईं। एनएसएस जीवन भर का अनुभव देता है।

कार्यक्रम में जनभागीदारी समिति के सदस्य, कॉलेज के कर्मचारी और बड़ी संख्या में एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

कपास की फसल पर दोहरी मार

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी जिले के कपास किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले लगातार बारिश और जलभराव ने फसलों को नुकसान पहुँचाया और अब गुलाबी इल्ली के प्रकोप ने रही-सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। खेतों में मुरझाती और खराब होती फसलें देखकर किसानों में भारी निराशा है।

किसान भागीरथ पटेल के मुताबिक, लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया, जिससे कपास के डोंडों (कच्चे फल) में सड़न और कालापन आ गया। उन्होंने कहा कि पहले प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल कपास का उत्पादन हो जाता था, लेकिन इस साल यह मुश्किल से 2 से 3 क्विंटल होने की उम्मीद है।

तलून गांव के किसान महेश धनगर ने बताया कि उन्होंने साढ़े तीन एकड़ में कपास की फसल लगाई थी, जिसमें प्राकृतिक आपदा और गुलाबी इल्ली ने पूरी फसल बरबाद कर दी। उन्होंने कहा, ÷एक झाड़ में तीन-चार इल्ली मिल रही हैं, जिससे फसल पूरी तरह खराब हो गई है।÷ किसान ने बताया कि साढ़े तीन एकड़ जमीन में करीब एक लाख रुपए का खर्च आया, जबकि उत्पादन प्रति एकड़ सिर्फ 2 से 2.5 क्विंटल हुआ है। उन्होंने सरकार से इसे प्राकृतिक आपदा मानकर मुआवजा देने की मांग की है।

किसान संजय यादव ने भी अपनी चार एकड़ की पूरी फसल गुलाबी इल्ली से खराब होने की बात कही। उन्होंने कहा, ÷पहले बारिश की मार थी, अब गुलाबी इल्ली की बीमारी ने फसल को बर्बाद कर दिया। उम्मीद थी कि इस बार 10 क्विंटल से ज्यादा उत्पादन होगा, मगर दो क्विंटल भी नहीं निकला।÷ किसान बताते हैं कि कर्ज लेकर फसल लगाते हैं लेकिन कभी आपदा, कभी बीमारी से फसल नष्ट हो जाती है, जिससे कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है।

किसानों को एक और बड़ा झटका विदेशी कपास पर घटाए गए आयात शुल्क से भी लगा है। उनका कहना है कि सस्ते आयात के कारण घरेलू बाजार में कपास का भाव गिर गया है। साथ ही भारतीय कपास निगम (बीसीसीआई) की खरीद में भी देरी होती है, जिससे किसानों को अपनी उपज को संभालकर रखने में दिक्कत होती है। जिले की मंडियों में कपास की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन खेतों से फसल निकालने में अभी 8 से 15 दिन का समय और लगेगा। इस दोहरी मार से जूझ रहे किसान गहरे आर्थिक संकट में हैं और उनकी नाराज़गी लगातार बढ़ रही है।

चुनावी सफर के साथ-साथ बदल रहा है राहुल का एजेंडा

बिहार में तीन दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस घर वापसी के लिए बेताब है। कांग्रेस के खिसकते जनाधार को दुबारा जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण के बहाने सामाजिक न्याय को सेट करने के लिए दांव चला। चुनाव की तपिश जैसे जैसे बढ़ रही है।राहुल गांधी की सियासी चाल भी बदलती जा रही है।

भाजपा निस्वार्थ सत्याग्रही है। कांग्रेस की महत्वकांशा भाजपा को पहले से मालूम है।कांग्रेस इतना घटिया आरोप लगा सकती है। यह चुनाव आयोग को भी मालूम नही था।एसआईआर की कांग्रेस की स्क्रिप्ट पर तेजस्वी भी शामिल हो गए। तेजस्वी ने एसआईआर के आंदोलन को संबल प्रदान करने के लिए वोटनीति और वोट चोरी के कथित आरोपो में कांग्रेस के साथ जुड़ गए। बिहार मे लोगो को भी प्रेरित किया। लेकिन इसकी असली वजह यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस का बिहार की राजनीति से जुड़ाव नीरस हो होता जा रहा है। तीन दशक का समय कम नही होता है। तीस साल के व्यक्ति को यह खबर भी नही होगी कि कांग्रेस भी कोई दल है। क्योंकि तीन दशक से बिहार में कांग्रेस सता से बाहर है। कांग्रेस की इस तरह के बेतुके सवाल और जवाब देखकर बाहर बसे भारतवंशी जिन्हें देश की उन पार्टियों से पीड़ा पहुंचती है, जिन्होंने ऐसे विकल्प को उठाया है, जिसका कोई वजूद नही है। देश मे किसी एक पार्टी के व्यक्ति से लोग इतने नाराज नही हुए होंगे, जितना कांग्रेस से। बहरहाल, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सभी आरोपो का खंडन किया है। सत्ता की राजनीति ने आकंठ डूबे राजनेताओ से गिरते राजनीति के स्तर में सुधार की उम्मीद नही की जा सकती है।कांग्रेस बारी बारी से राज्यो और केंद्र में ग्यारह वर्षो से सत्ता से दूर रहने के कारण छटपटा रही है। जूठे आरोप से ही अगर सत्ता मिलती है तो क्या हर्ज है? अपने कार्यकाल में कर्मठता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की झलक देखने को मिलती है तो मतदाता कभी भी नेता और पार्टी को सत्ता के गलियारों तक पहुंचा सकते है।लोगो को साफ सुथरी राजनीति की जरूरत है। उसी दल या नेता ओ के लिए रात्रि जागरण का कार्य करते है, जो राजनीति में दूध की तरह सफेद है। ऐसे चुनिंदा लोग राजनीति में है, जिनके लिए मतदाता भरोसा भी करता है और पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए तैयार रहते है। लोक जागरण के कार्य के लिए जनता को भरोसा होना बहुत आवश्यक है। राहुल और तेजस्वी के पीछे कोई तीसरा हाथ है,यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मोदी मिशन के इस एजेंडे को धराशायी करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे है। कर्नाटक में राहुल ने उन वोटरों को समक्ष खड़ा कर कहा गया कि इन लोगो के नाम मतदाता सूची में काट दिया गया है।राहुल के बेबुनियाद आरोपो से निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के सभी आरोपो को दिशाहीन और जूठे बताए। बिहार में पैर जमाने और सत्ता का स्वाद चखने के लिए राहुल ने एसआईआर को ही केंद्र बिंदु नही बनाया है, उसके पूर्व बिहार में पलायन, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सियासी बिसात बिछाने में जुटी थी।कांग्रेस जाति धर्म,

बाहुबल और तुष्टिकरण की नीति पर चुनाव जीतने की जुगत में है। इसलिए वह ऐसे लोगो को खड़ा कर रही है,जिसका कोई विरोध नहीं करता है। हालांकि, बिहार में राजनैतिक तौर पर कांग्रेस पहचान बना पाई है और न ही राजद उस धुरी तक पहुंच गई है, जो बिहार में कुछ उम्मीद छोड़ सके।कांग्रेस अपना एजेंडा ओबिसी, दलित और अल्पसंख्यक वोटो के इर्द गिर्द बुन रही है। कांग्रेस ने जिन बेबुनियाद मुद्दे उठाए है इसके लिए मतदाता क्या सोचते है ? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस अपने कुनबे को जोड़ने का प्रयास कर रही है,वही कांग्रेस को वजूद बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कांग्रेस अब बिखरा हुआ दल है। कांग्रेस का भूतकाल खण्डित रहा है। कांग्रेस पर आजादी के बाद से अनगिनत आरोप लगे है। इससे मतदाता सोच समझकर फैसला करता है। आज के मतदाता सोच समझकर निर्णय लेते है।कांग्रेस की स्थिति बिहार में आश्वासन देने की नही रही है। प्रदेश संगठन की कमान भूमिहार नेता से लेकर दलित समाज के नेता को सौंप दी है। बिहार में नीतीश को सुशासन बाबू का तमगा मिला हुआ है। बिहार को कांग्रेस ने फटेहाल स्थिति में छोड़ दिया था। उसके बाद लालू ने 15 साल तक राज किया और बिहार को नरकगामी बना दिया। जंगल राज की राजनीति खत्म होते ही मतदाताओ ने नीतीश बाबु का दामन थाम लिया और अब फिर से कांग्रेस बिहार की सत्ता के गलियारों तक पहुंचने के लिए कुतर्क का सहारा ले रही है।

तीस साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस ने कोई सबक नही सीखा है। कांग्रेस उसी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है, जिसको तीन दशक पहले छोड़ आई थी।बिहार में कांग्रेस वापसी के लिए इस कदर बेचैन है कि वह हर हालत में सत्ता हासिल करना चाहती है। और इसके लिए गठबंधन भी करना पड़ेगा तो उसे मंजूर है। बिहार के चुनाव आयोग की एसएआर की सियासी चाल बदल दी है।

निर्वाचन आयोग पूरे देश मे एसएआर लगाने की कवायद शुरू की है। देश मे मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण समय की मांग है। बिहार के सियासी खेल में अन्य दलों के नेताओ ने हिस्सा लिया और इस रोमांस का लुफ्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्तालिन ने भी उठाया।कांग्रेस का फोकस अब वोटनीति और वोट चोरी पर केंद्रित है।वोटनीति और वोट चोरी के शोरगुल में अहम मुद्दे छूटते दिखाई दे रहे है। राहुल ने सबसे पहले समाजिक न्याय का मुद्दा उठाया था जिसमे जातिगत मतगणना और दलित पिछडोका मुद्दा उठाया।कांग्रेस की सियासी चाल से बिहार में ठंडे पानी मे उबाल देखने को मिल रहा है। मोदी के जन्म दिवस पर बिहार में एक मंच पर बिहार के मतदाताओं को नीतीश कुमार ने मोदी से हाथ जोड़कर नमस्ते करने का आग्रह किया और एक ही क्षण में हजारो हाथ खड़े हो गए। बिहार में मोदी की लोकप्रियता कम नही हुई है। तब सवाल यह उठता है कि एकाएक कांग्रेस का सियासी रथ कहा जाकर रुकेगा। क्योकि कांग्रेस के पास कोई ऐसे मुद्दे नही है, जिससे नीतीश कुमार के सुशासन बाबू का तमगा छीना जा सके। इस बीच तेजस्वी ने राह बदल दी है। क्योंकि वोटचोरी का मुद्दा बिहार में असरदार नही दिख रहा है। क्योंकि चुनाव आते आते लोग इस मुद्दे को भूल जाएंगे। इस बीच तेजस्वी ने अधिकार यात्रा शुरू की है। बिहार के इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस के आरोप खारिज करते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली गई थी। उधर, मोदी ने बिहार की सभा से कहा कि घुसपैठियों को बिहार से निकालकर रहेंगे।

कांतिलाल मांडोत

केबिनेट मंत्री ने विकास कार्यों के भूमिपूजन के साथ किया उद्घाटन

माही की गूंज, बरझर। फिरोज खान

केबिनेट मंत्री नागरसिह चौहान ने च.शे. आजाद नगर के बड़गांव, बरझर, रिंगोल व बडा खुटाजा में विकास कार्यों का भूमिपूजन किया और भाजपा के किए वादों को गिन-गिनकर वर्तमान में चल रही योजनाओं के बारे में बताया व उसका फायदा आगे आकर लेने की बात कही।

ग्राम पंचायत बड़गांव में केबिनेट मंत्री नागरसिह चौहान ने 5 लाख 40 हजार से बिजली ग्रिड उद्घाटन अवसर पर कहा कि, भाजपा का विधायक और कांग्रेस के विधायक में अन्तर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज जोबट क्षेत्र की विधायक क्षेत्र में ध्यान ही नहीं दे रही है। आज हमने आपके क्षेत्र में बिजली ग्रिड, सड़कों से लेकर अनेक काम भाजपा कर रही है। अब नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रही है। आप लोग शराब, मटन का सेवन ना कर उपास वृत रखकर माता की नवरात्रि त्योहार भक्ति में लिन हो जाने को लेकर कहां। पहाड़ी पर बने बरझर में पानी की टंकी से शिव मंदिर का खरजा निमार्ण 7 लाख 50 हजार रुपए व बिजली खंबे स्टेंट लाइट के भूमिपूजन पर कहा भी कही। साथ ही बताया कि, आज देश के प्रधानमंत्री ने खाने-पीने सहित सीमेंट, सरिया सहित 135 वस्तुओं पर जीएसटी को कम कर दिया है जिससे आप सभी को फायदा होगा।

साथ ही नागर सिंह चौहान ने रिंगोल में भी तीन बिजली डीपी का उद्घाटन किया और महिलाओं से कहा कि, लाड़ली लक्ष्मी योजना के 1250 रू मिलते हैं और हमारी सरकार ने राखी पर बहनों को 1500 रू दिए और अब भाजपा की सरकार दिपावली पर्व के भाईदूज पर हर माह 15 सौ रुपए देगी और विधानसभा चुनाव तक 3 हजार रुपए देने का वादा पुरा भी करेगी। इस दौरान माधवसिंह डावर ने कहा, भाजपा जो कहती हैं वह करती है। आज भाजपा के कार्यकाल में हर तरह पक्की सड़क हर गांव-गांव पक्के मकान कुएं यह सब भाजपा की देन है। बड़गांव में तालाब नहर की मांग रखी जिसे नागरसिंह चौहान ने आश्वासन दिया जल्द मांग पूरी करने का भरोसा दिलाया।

इस अवसर ज़िला उपाध्यक्ष मनीष शुक्ला, मण्डल अध्यक्ष बरझर लालसिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष जगदीश गणावा, धमेंद्र जयसवाल, बरझर सरपंच हिमसिग बारिया, बड़गांव सरपंच श्रीमती गोहिल, रिंगोल सरपंच महेश भूरिया, बोरकुण्डिया विक्रम ढाक, शांतिलाल प्रजापत, कपील सोनी, धन्ना लाल प्रजापत, सुरेश पंचाल, मांगीलाल प्रजापत, शंकर लाल राठोड़, चंदूलाल साहू आदि मौजूद थे।

छात्रावास में 59 बच्चियां बीमार, प्राचार्य सहीत बीईओ व बीआरसी पर कार्रवाई की माँग

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कठ्ठीवाड़ा के माता सबरी आवासीय कन्या आश्रम में रविवार को 59 बच्चियों की हालत अचानक बिगड़ने से हड़कंप मच गया। बच्चियों को फूड पॉयजनिंग की शिकायत के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ की स्थिति गंभीर बताई गई। घटना की जानकारी मिलने पर जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल तत्काल अस्पताल व छात्रावास पहुँचीं। निरीक्षण के दौरान विधायक ने आश्रम की व्यवस्था को बेहद लचर पाया। उन्होंने बताया कि रसोईघर में सड़ा हुआ व कीड़ों वाला आटा, खराब सब्ज़ियाँ, इल्लियों वाले पोहे और एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई। बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा था। परिसर में शौचालय-बाथरूम की स्थिति भी दयनीय मिली, वहीं बच्चों ने स्टेशनरी की कमी की शिकायत भी की।

विधायक पटेल ने कहा कि, सिर्फ वार्डन को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आश्रम और स्कूल के प्राचार्य शंकरलाल जाटव (साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी), खंड शिक्षा कार्यालय और खंड स्त्रोत समन्वयक भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया और लापरवाही बरती।

इस संबंध में विधायक सेना महेश पटेल ने माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई करने की माँग की है। पत्र की प्रतिलिपि जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव और कलेक्टर अलीराजपुर को भी प्रेषित की गई है। विधायक ने कहा कि, यदि दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे हादसे दोबारा भी हो सकते हैं।

लोकायुक्त ने कनिष्ठ पूर्ति अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

माही की गूंज, अलीराजपुर।

इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने आलीराजपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रामा अवास्या को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रामा अवास्या ने आजाद नगर बरझर के सामलाकूड में एक समूह की महिला से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। महिला ने इसकी शिकायत इंदौर लोकायुक्त टीम से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया।

अधिकारी रामा अवास्या ने महिला को पैसे लेकर वेयरहाउस बुलाया था। जैसे ही महिला तय जगह पर पहुंची और उसने अधिकारी को रिश्वत दी, लोकायुक्त टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। समाचार लिखे जाने तक लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही थी।

विधायक ने विद्युत डीपी के उद्घाटन के साथ मंत्री चौहान पर साधा निशाना

माही की गूंज, जोबट।

विधानसभा क्षेत्र के बारी फलिया मे विधायक सेना महेश पटेल ने नवनिर्मित विद्युत डीपी का उद्घाटन किया। यह डीपी विधायक निधि से लगभग 5 लाख 18 हजार रुपए की लागत से स्थापित की गई है। उद्घाटन अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का ढोल-ढमाकों और फूलमालाओं से स्वागत किया व इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएँ, कार्यकर्ता और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इस दौरान विधायक ने कहा कि, हमारी प्राथमिकता गाँव-गाँव तक विकास पहुँचाना है। बिजली की बेहतर सुविधा ग्रामीणों की बुनियादी ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखकर यह डीपी लगाई गई है। आने वाले समय में क्षेत्र की हर फालिया और गाँव तक मज़बूत बिजली व्यवस्था पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

मंत्री पर साधा निशाना

विधायक पटेल ने मंत्री नागर सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया और कहा, मंत्री जी जिस विभाग के मंत्री हैं, वहाँ काम नहीं हो रहा। उन्हें बस साइकल वितरण करते देखा जाता है, असली काम नहीं होता। आए दिन किसी अन्य विभाग या पंचायत के कार्य का फीता काटते रहते हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास में योगदान दिखाई नहीं देता।

इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता फतेसिंह काछवा, नावेल काका, भूरीबाई रायसिंह सरपंच, ब्लॉक अध्यक्ष कालू मेड़ा, सरदार अजनार, कंदा सरपंच दिलीप, अरविंद डावर, मोनू बाबा, जीतू अजनार जनपद सदस्य, वेरसिंह पटेल, सुरेश भाई (रामपुर), सोयब खान, सुंदर, निहाल सिंह भंवर, अराम पटेल,

अमर सिंह पटेल सरपंच, भंगू सरपंच, लक्की राठौर, दिलीप चौहान सरपंच, सोमला रावत सरपंच, कदम रावत सरपंच, लाखन रावत सरपंच, अशोक चौहान, कैलाश बड़ीहीरापुर सरपंच सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

सफाई मित्रों का किया स्वास्थ्य परीक्षण

माही की गूंज, बरझर।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत बरझर में सफाई मित्र सुरक्षा एवं कल्याण शिविर रखा गया। जिसमे ग्राम पंचायत बरझर में सफाई मित्रों और ग्रामीणों को सरपंच हिमसिंह बारिया एवं गमसिंह मेड़ा ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छता के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। सचिव शंकरसिंह बामनिया की उपस्थिति में सरपंच हिमसिह बारीया के द्वारा सफाई मित्रों को सम्मान एवं डॉ. अमित शर्मा के द्वारा सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

सरपंच हिमसिंह बारिया और गमसिंह मेड़ा ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले अभियान अंतर्गत ग्रामीणों ओर सफाई मित्रों को स्वच्छता अभियान अंतर्गत साफ सफाई रखने, शौचालय का उपयोग करने, नवीन परिवार को शौचालय का निर्माण कर उसका उपयोग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की आदि की सलाह दी।

सांसद खेल महोत्सव में 2 अक्टूबर तक कर सकते है पंजीयन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

क्षेत्रीय सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में सांसद खेल महोत्सव के संबंध में बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिंह ने बताया कि पंजीयन की दिनांक 2 अक्टूबर तक रहेगी उसके पश्चात मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले खेल है रस्सी कशा- काशी, नींबू रेस , गिल्ली डंडा चेयर रेस एवं गिल्ली डंडा, खो-खो कबड्डी एवं तीरंदाजी फुटबॉल एवं क्रिकेट, दौड़, एवं दिव्यांगजनों के लिए आर्म रेसलिंग एवं शतरंज रहेगा।

इस दौरान श्रीमती चौहान ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि, जिले के युवाओं में खेल भावना जगाने और ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को खोजने के साथ साथ उन्हें राज्य स्तरीय पहचान देने के लिए सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन जिले में किया जा रहा है। हम सभी को इस उत्सव के दौरान अधिक से अधिक खिलाड़ियों को पंजीयन करवाना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी युवाओं को खेल मे भी प्रोत्साहन मिले। इस खेल महोत्सव मे उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं जिसके कारण युवाओं के साथ माता बहन एवं आमजन भी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते है। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारी से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र के युवा रनिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन करते है निश्चित ही इन खिलाडियों का स्टैमिना अच्छा होने से हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते है हम लोगों को उन्हें प्रोत्साहित कर इनकी खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करना चाहिए। हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ छात्र छात्राओं एवं खिलाड़ियों का अधिक से अधिक पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

इस दौरान संयुक्त कलेक्टर मनोज गरवाल, अनुविभागीय अधिकारी वीरेन्द्र सिंह बघेल, तपीस पांडे, सुश्री निधि मिश्रा, समस्त मुख्य कार्यपालन जनपद सहित खेल विभाग, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

दशहरा पर्व में रावण दहन को रोकने के लिए लगे पोस्टर

माही की गूंज, उज्जैन। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, यहां पर धर्म और आस्था का अलग ही आकर्षण होता है। लेकिन अबकी बार दशहरे के अवसर पर होने वाले रावण दहन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के कई प्रमुख इलाकों के आसपास कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर रावण दहन का विरोध जताया गया है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन को रोकने के लिए कई जगह पोस्टर लगा दिए हैं।

रावण एक महान विद्वान थे, उनका दहन परंपरा के नाम पर अपमान

इन पोस्टरों में लिखा गया है कि 'रावण एक महान विद्वान थे, उनका दहन परंपरा के नाम पर अपमान है।' स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार सुबह जब लोग दशहरा आयोजन की तैयारियों में लगे हुए थे, तब पोस्टर दिखाई दिए। कुछ धार्मिक संगठनों ने इसे सांस्कृतिक परंपराओं पर हमला बताया और कड़ी प्रतिक्रिया दी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रावण दहन न केवल रामायण की परंपरा का हिस्सा है, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक भी है।

इतिहास या रामायण में कहीं भी रावण दहन का जिक्र नहीं

दरअसल, पूरा मामला तब गरमा गया जब, उज्जैन के परशुराम मंदिर में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज की बैठक हुई थी। इस दौरान रावण दहन का विरोध करने का फैसला लिया गया। महाकाल सेना ने खासतौर पर ब्राह्मणों से अपील की है कि वे रावण दहन जैसे आयोजनों में हिस्सा न लें ।

ग्राम के बॉक्सरो ने इंदौर में जीते पदक

माही की गूंज, आम्बुआ।

संभागीय शालेय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में माँ पार्वती मेमोरियल स्कूल आम्बुआ के छात्रो ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, दो रजत और दो कास्य पदक जीते।

माँ पार्वती मेमोरियल स्कूल की बॉक्सिंग कोच शाहीन मकरानी ने बताया की इंदौर के नेहरू स्टेडियम में दो दिवसीय संभागीय शालेय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। जिसमे विभिन्न वर्ग श्रेणी के संभाग के लगभग 200 बॉक्सरों ने प्रतियोगिता में सहभागिता की थी। जिसमे ग्राम के विद्यालय के छात्र 40-42 किलोग्राम में तनवीर खान प्रथम स्वर्ण, रुद्र राठौड़ दितीय सिल्वर, लकी असोरिया तृतीय कास्य पदक जीता जबकि 30-32 किलोग्राम वर्ग में लव राठौड़ एवं यशराज सिसोदिया ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कास्य पदक जीतने में सफल रहे।

विद्यालय के बच्चों के पदक जीतने पर स्कूल डायरेक्टर गोविंदा माहेश्वरी व विद्यालय प्राचार्य दीपांशी माहेश्वरी व समस्त स्टाफ के द्वारा बच्चों का ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत व साफ़ा मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया।

आज भी बड़े बुजुर्ग आयुर्वेद पर करते है पूर्ण विश्वास- मंत्री चौहान

माही की गूंज, अलीराजपुर।

ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग आयुर्वेद पर बहुत भरोसा करते हैं, आदि अनादि काल से आयुर्वेद बीमारियों को जड़ से समाप्त करने का कार्य करता आ रहा है। पहले हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियों के नाम ही नहीं सुने थे, किन्तु अब आधुनिकता के साथ लापरवाहियों के चलते लोग कई बीमारियों के शिकार होते जा रहे। कोविड के दौरान भी आयुर्वेद ने कईयों के प्राणों की रक्षा की है। ये बात आज कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।

जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, विधायक प्रतिनिधि गोविंदा गुप्ता, भाजपा जिला मंत्री एवं पूर्व नपा अध्यक्ष रितेश डावर द्वारा भगवान धनवंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पूजा कर शिविर का शुभारंभ किया गया। जिसमें 182 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री चौहान ने आयुर्वेद के महत्व को समझते हुए मौजूद आमजन को छोटी से छोटी और किसी भी बीमारी की स्थिति ने सीधे शासकीय प्राथमिक सामुदायिक एवं जिला अस्पतालों में डॉक्टरों से परीक्षण करवाने की अपील करते हुए अपना संबोधन दिया। शिविर में डॉ. देवेंद्र सुनहरे सीएमएचओ, डॉ. प्रकाश ढोके सिविल सर्जन, डॉ. हीरालाल ठाकुर जिला आयुष अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शिविर में आयुर्वेदाचार्य डॉ. वरुण श्रॉफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र का वाचन किया।

शिविर में डॉ. जितेंद्र मकवाने, डॉ. सपना राठी, डॉ. ज्योति पटेल के वात रोग, उदार रोग, त्वचा रोग ,स्त्री रोग, श्वास रोग आदि रोगों के मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवाइयां वितरित की।

कार्यक्रम समापन पश्चात कैबिनेट मंत्री चौहान ने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सेल्फी प्वाइंट पर अपना फोटो भी लिया। उक्त जानकारी आयुष विभाग द्वारा दी गई।

अब भी अंधविश्वास के अंधकार से जकड़ा जिला, मासूमों की जान दाव पर...?

प्रशासनिक कवायदें सिर्फ कागजी घोड़े ही साबित होती दिखाई पड़ती है

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसूरी

फाईल फोटो

आजादी के लगभग आठ दशक बीतने को है मगर मध्यप्रदेश के ठेठ पश्चिमी छोर पर बसे आदिवासी जिले में अब भी अंधविश्वास का भारी बोलबाला है। वजह यह भी कि, आजादी के इतने समय बाद यहां शिक्षा, जागरूकता, समृद्धी और सम्मानजनक जीवन यापन अब भी दीवा स्वप्न ही साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे गरीब जिलों में अब भी आलीराजपुर और झाबुआ का नाम पहले और दूसरे स्थान पर है। जबकि जारी सरकारी आंकड़े इन जिलों में शिक्षा के सुधार को उपलब्धी गिनाते नहीं थकते। गरीबी का आलम यह है कि, जिले से अब भी रोजगार के नाम पर पलायन जारी है और यह इतना है कि गांव के गांव रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते है। मगर सरकारी आंकड़ों में जिले की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत ही नजर आती है। यहां ना तो सही ढंग से ग्रामीणों को शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है और ना ही स्वास्थ्य। यहां के ग्रामीण आदिवासी आए दिन किसी न किसी असुविधा के लिए सरकारी दफ्तरों को घेरते और आंदोलन करते दिखाई देते है। शिक्षा का आलम ऐसा कि विद्यार्थियों को अपनी जरूरतों के लिए पढ़ाई छोड़कर आंदोलन करने पड़ते है। सरकार ने यहां ग्रामीण आदिवासियों के लिए यूं तो कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है, लेकिन जागरूकता के अभाव और अंधविश्वास के चलते यह सारी सुविधाएं समय आने पर शुन्य ही साबित होती है। सोने पर सुहागा तब होता है जब इन सारे मामलों में अधिकारियों की लापरवाहीयां उजागर होती है। अपनी कमियों को उजागर होता देख प्रशासन भी फरियादियों को रोकने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगाता और पुलिस का सहारा लेते नजर आता है।

हाल ही में जिला मुख्यालय पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने जिले में फैली अशिक्षा और अंधविश्वास से एक बार फिर पर्दा उठा दिया है और प्रशासनिक सुविधाओं और कार्यप्रणाली को धत्ता साबित कर दिया है। कहने को तो जिला मुख्यालय पर सर्वसुविधा युक्त जिला चिकित्सालय है। इस जिला चिकित्सालय में तरह-तरह के प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर मौजूद है। मगर कई बार यह जिला चिकित्सालय भी कई असुविधाओं के चलते अखबारों की सुर्खियों में नजर आता है। विडम्बना यह कि, इतना बड़ा अस्पताल जिले में होने के बावजूद जिले के ग्रामीण जिले से सटे अन्य प्रदेशों में इलाज के लिए जाना ज्यादा उचित समझते है या फिर अंधविश्वास के चलते बड़वे-भोपों के चक्कर में पड़कर अपनी जान से खिलवाड़ करते है। यहां एक बात तो बिल्कुल साफ है कि, सरकारें चाहे जितनी सुविधाएं यहां उपलब्ध करा दे लेकिन जब तक लोगों में इन सुविधाओं को लेकर विश्वास और जागरूकता नहीं जगा पाती तब तक स्थिति ढाक के तीन पात ही साबित होगी। जिले से अधिकतर ग्रामीण और शहरी लोग गुजरात के दाहोद सिर्फ अपने इलाज के लिए जाते है, जब उनसे यह पूछा जाता है कि, यहां पर भी तो अस्पताल है। तो वे कहते है कि, अस्पताल तो है लेकिन इलाज और व्यवस्थाएं ठीक नहीं है इसलिए गुजरात जाते है। मतलब सीधा सा है कि, जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग अब भी जिलेवासियों को यह विश्वास दिलाने में नाकाम रहा है कि, उन्हे जिले में ही जिला चिकित्सालय में अच्छा उपचार उपलब्ध हो सकता है। नतीजा यह निकल कर सामने आ रहा है कि, जिले के ग्रामीण आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी अंधविश्वास में जकड़े होकर अपना व अपने बच्चों का इलाज डॉ. से ना करवाते हुए बड़वे-भोपों से करवा रहे है।

ताजा मामला जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में ही देखने को मिला। जहां महज 48 घंटों में तीन ऐसे बच्चे उपचार के लिए पहुंचे जिन्हे निमोनिया की शिकायत थी। मगर इन बच्चों के परिजनों ने बच्चों के बीमार होने पर पहला विश्वास बड़वों और तांत्रिकों पर जताया और बड़वों से मासूम बच्चों के सीने पर गर्म सरियों से दाग लगवाया। स्थिति बिगड़ने के बाद वे अपने बच्चों को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। हालांकि इन बच्चो में दो माह से लेकर 2 साल तक के बच्चे शामिल है। डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था में बच्चों का उपचार शुरू भी कर दिया। हम कामना करते है कि, ये तीनों बच्चे जल्द स्वास्थ्य हों... लेकिन अब जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासन के जागरूकता अभियानों पर सवाल बहुत से है।

क्या यह नहीं होना चाहिए था कि, बच्चों के बीमार होने पर परिजनों का पहला विश्वास जिले के स्वास्थ्य विभाग और उसके डॉक्टरों पर होना चाहिए था...? आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि, परिजन अपने बीमार बच्चों को लेकर पहले बड़वे या तांत्रिक के पास पहुंचे डाक्टरों के पास नहीं...? क्या यह प्रशासन की विफलता नहीं है कि, आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी जिले के ग्रामीणों को अंधविश्वास से मुक्ति नहीं मिल पाई...? आखिर क्यों इतने दशकों बाद और इतनी स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद स्वास्थ्य विभाग जिले के ग्रामीणों में विश्वास नहीं पैदा कर पाया..? या फिर यह मान लिया जाना चाहिए कि, प्रशासनिक तंत्र में बैठे अधिकारी जिले में सिर्फ और सिर्फ माथा उतारनी ही करने के लिए बैठे है।

एक तरफ तो कलेक्टर, मोटीआई जैसे अभियानों को प्रमोट करती नजर आती है। इसके लिए वे प्रदेश व राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार भी पाती है, लेकिन विडम्बना कि, उसके उलट जिले में अब भी अंधविश्वास अपने पूरे जोर पर है। जहां बीमार होने पर अब भी बच्चों को बड़वे और तांत्रिक गर्म सरियों से दागते है। यह उन अधिकारियों के मुंह पर खुला तमाचा है जो मोटीआई अभियान का ढिंढोरा पीटते नहीं थकते।

ऐसा नहीं है कि, बीमार बच्चों को दागने का जिले में यह कोई पहला मामला है। इससे पहले भी लगातार हर वर्ष जिले में कहीं न कहीं से इस तरह की खबरें सुनने को मिल ही जाती है। 2023 में जब इस तरह का मामला सामने आया था तब मानवाधिकार आयोग ने इस पर जिले के आला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की थी। तत्समय निमोनिया ग्रसित बच्चों को दागने वाले बड़वों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन वर्तमान में मामला सामने आया है उसने स्थिति को ढाक के तीन पात साबित कर दिया है। यह भी साबित कर दिया है कि, अधिकारी यहां जिले को सिर्फ प्रयोगशाला मानकर ही आते है, नित नए प्रयोग करते है, अवार्ड-रिवार्ड लेते है और चल देते है। उन्हे जिले की गरीब जनता से कोई लेना-देना नहीं है। पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि, इस तरह निमोनिया ग्रसित बच्चों को दागने के मामले जिले के पिटोल, कल्याणपुरा, राणापुर और अब झाबुआ जैसे क्षेत्रों में देखने को मिले है। यह भी चिंता का ही विषय है कि जिला मुख्यालय के आसपास 5-10 किलोमीटर के दायरे में बसे ग्रामीण ही इस बार बच्चों को गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे है, जिनके शरीर पर बड़वों, तांत्रिकों द्वारा गर्म सरिये से दागने के निशान मौजूद है। हालांकि चिकित्सकों ने लिखित में इसकी सूचना पुलिस को दी है।

मगर सवाल तो सवाल है उठेंगे...! क्या कलेक्टर को इस तरह के मामलों को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए...? जिस तरह मोटीआई अभियान का ढिंढोरा पीटा गया क्या उसी तरह अंधविश्वास के खिलाफ कलेक्टर को अभियान नहीं छेड़ना चाहिए...? जिस तरह जागरूकता के अभाव में ग्रामीण परीजन अपने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए बड़वों और तांत्रिकों को प्राथमिकता दे रहे है... क्या उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए...? हालांकि हो सकता है कि, इस अभियान में कलेक्टर को कोई मेडल या सम्मान ना मिले, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ अभियान की शुरूआत होती है तो यह मान लिजिए कि परीणाम सकारात्मक ही आएंगे। मेडल मिले ना मिले लेकिन दुआएं जरूर मिलेगी।

दूसरी तरफ जिले के जनप्रतिनिधि जो खुद आदिवासी होकर कई तरह के अभियान समाज की कुरितियों को दूर करने के लिए चला रहे है उन्हे भी यह शुरूआत करनी होगी। जिस तरह से जिले में थ्री डी अभियान चलाया गया उसी तरह अंधविश्वास और बड़वों-तांत्रिकों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाना चाहिए। क्योंकि अंधविश्वास में फंसकर नुकसान आदिवासी समाज का ही हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों को बड़वों-भोपों के जाल से सुरक्षित कर शिक्षा की ओर ले जाना बहुत जरूरी है। जिससे भविष्य में आदिवासी समाज और जिले की दशा और दिशा में सुधार आने की प्रबल संभावना है।

अपनी सुरक्षा अपने हाथ, जिले में कानून है या जंगल राज...!

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो एक जमाना गुजर गया जब जिले में बदमाशों का खौफ हुआ करता था। उस समय जिले में डकैती, राहजनी, चोरी और लूट आम बात हुआ करती थी, लेकिन धीरे-धीरे जिले की कानून व्यवस्थाओं में सुधार हुआ और इन घटनाओं पर अंकुश लगा था। पूर्व में जिले में आने वाले पुलिस अधीक्षकों की कार्यप्रणाली इतनी मुस्तैद थी कि, जिसने अपराधियों को खौफ में डालकर आमजनों को राहत दिलाई थी। धीरे-धीरे जिले में फिर से कानून व्यवस्थाएं लचर होती जा रही है और इसके परीणाम भी देखने को मिल रहे है। जिले में नए आने वाले पुलिस अधिकारियों ने पुलिसिंग के तरीके बदले और पूरी तरह से सामाजिक पुलिसिंग को आगे रखा। पुलिसिया सख्ती कम होने लगी और अपराधियों के हौंसले बुलंद होने लगे। पिछले कुछ वर्षों में जिले में आए पुलिस अधीक्षकों ने पुलिसिया रौब छोड़कर सामाजिक पुलिसिंग को इतना बढ़ावा दे दिया जिससे जिले में अपराधियों को कानून व्यवस्था में लचरता नजर आने लगी है और वे एक बार फिर से अपनी हरकतों को अंजाम देने में लग गए है।

सोमवार रात जिला मुख्यालय पर हुई एक घटना ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए है। वैसे तो पुलिस की रात्रि गश्त साल भर चलती रहती है, लेकिन इनसे कितनी घटनाओं को रोकने में कामयाबी मिलती है यह तो पुलिस विभाग ही जाने। सोमवार रात जिला मुख्यालय से सटे ग्राम बीलीडोज में बदमाशों ने एक लूट को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की। बदमाशों ने एक फार्म हाउस को लूट की नियत से निशाना बनाते हुए दरवाजे तोड़े और अंदर घुस गए। जब बदमाशों ने घर पर धावा बोला उस समय एक ही परिवार के पांच सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। रात करीब डेढ़ बजे नकाबपोश बदमाशों ने मय हथियारों के धावा बोला। बदमाश दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। दरवाजा टूटने की आवाज से घर के सभी सदस्य जाग गए। जब देखा तो बदमाश दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए थे। इनमें से कुछ के पास देशी कट्टे थे तो कुछ के हाथों में लोहे की राड़ थी। जब घर मालिक ने इनका विरोध किया तो वे मारपीट करने लगे। घर में मौजूद लोगों ने उनका जमकर मुकाबला किया और बदमाशों को घर के बाहर धकेलकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जिसके बाद उन्होने डायल 112 पर फोन कर मदद मांगी। पुलिस की कोई मदद पहुंचती उसके पहले ही बदमाश वहां से रफुचक्कर हो गए। मंगलवार को इस घटना की रिपोर्ट झाबुआ थाने पर की गई। हालांकि इस घटना में बदमाश कोई भी सामान नहीं ले जा सके।

इस घटना ने यह साफ कर दिया कि, अब आप पुलिस के भरोसे सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथ होती है। जिला मुख्यालय के समीप हुई इस घटना ने पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए है। जबकि पुलिस विभाग की रात्रि गश्त साल के बारह महीनें शहर की सुरक्षा में लगी रहती है। बावजूद इसके इस तरह की घटना होना कई प्रश्न खड़े कर रही है। इस घटना में अगर परिवार के सदस्यों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद यह घटना किसी बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाती। इस घटना से यह साबित होता नजर आता कि, जिले में कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि ''अपनी सुरक्षा अपने हाथ, जिले में कानून है या जंगल राज''...!

वर्तमान में नए पुलिस अधीक्षक को जिले में आए एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ है। अब तक यह देखने को नहीं मिला है कि, नए पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली कैसी है। हालांकि उनके किस्से बहुत सुने गए है। प्रदेश के अन्य जिलों में उनकी कई उपलब्धियों ने उन्हे सुर्खियों में रखा है। अब जिलेवासियों को भी काफी उम्मीदें है कि, नए पुलिस अधीक्षक जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने में अपनी विशेष रूची दिखाएंगे।

मकान एवं जमीन का मुआवजा किसान कार्यालयों के लगा रहे चक्कर

करोड़ों की लागत से बने तालाब का 4 वर्ष बाद भी नहीं मिला मुआवजा, जन सुनवाई में भी नही हुआ निराकरण

माही की गूंज,
पेटलावद/झकनावदा।

ग्राम बखतपुरा में जल संसाधन विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया के द्वारा वर्ष 2021-22 के अंतर्गत तालाब का निर्माण कराया गया जिसके निर्माण से ही तालाब के आसपास लगी भूमि किसानों की डूब क्षेत्र में आने से कृषि कार्य बंद हो चुका है। जिसके एवज में शासन द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए था। लेकिन 4 वर्ष होने के बाद भी शासन द्वारा किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

रमेश भूरिया, डूंगरसिंह, शंकरसिंह, रामसिंह,कालूसिंह, उमरावसिंह, हेमराज, उदयसिंह, कान्हा गोविंद, तुलसीबाई, पांचुड़ीबाई, बाबूसिंह,दर्जन भर किसानों ने बताया कि, जल संसाधन विभाग के माध्यम से कुंडियावाला नाका तालाब का निर्माण किया गया ,जिसमें से 65 किसानों की जमीन एवं मकान डूब में गए हैं। शासन द्वारा आज तक इन लोगों का मुआवजा तय नहीं किया गया है। जिसके कारण आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि, विभाग द्वारा तालाब के सर्वे के दौरान किसानों की भूमि एवं मकानों का भी सर्वे किया गया था जिसके समस्त कागजात विभाग को दिए जा चुके हैं लेकिन आज तक 4 वर्ष पूर्ण होने आए हैं इन्हें मुआवजा शासन द्वारा नहीं मिला है। इनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन कम थी वह भी डूब चुकी दूसरी जमीन नहीं होने के कारण खाने के लाले पड़ गए हैं। मजदूरी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है मजदूरी नहीं मिलने के कारण रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। संपूर्ण जमीन डूब क्षेत्र के कारण अब उनके पास कोई जमीन नहीं बची है। मुआवजा की आस लगाए बैठे किसान शासकीय विभागों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। किसानों ने बताया कि, जनसुनवाई मे 6 से 7 बार आवेदन दिए जा चुके हैं आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ शासकीय कार्यालयो के चक्कर लगाकर थक चुके हैं।

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री विपिन पाटीदार ने बताया कि, बखतपुरा किसानों के मुआवजा प्रकरण विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद को भेजे गए हैं, वहां से प्रकरण कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में आएंगे कार्यालय से चेक के द्वारा भुगतान किसानों को किया जाएगा।

जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र डावर ने बताया कि, कुंडिया वाले तालाब का मुआवजा के लिए सभी किसानों के कागजात सबमिट कर दिए गए हैं । कुछ किसानों का मुआवजा कर दिया गया है तथा कुछ बचे हैं इनकी भी कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई के लिए समस्त कागजात कलेक्टर कार्यालय झाबुआ को भिजवाए जाएंगे।

शराबी चालक बना देता जीप को हत्यारी

माही की गूंज, खवासा।

शराब के नशे में किसी भी तरह का वाहन चलाना अपराध है और पुलिस प्रशासन भी नशा मुक्ति पखवाड़ा व यातायात पखवाड़े के तहत शराब पीकर वाहन नहीं चलाने का संदेश देती है। साथ ही चालानी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन यह कार्रवाई महज मुख्य ग्राम या शहर में देखने को मिलती है तथा अखबारों में प्रेस नोट के माध्यम से समाचार प्रकाशित करवाकर प्रशासन अपनी वाहवाही लुटती है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में न हीं इसकी कोई कार्रवाई होती है और न ही कभी कोई वाहनों की चेकिंग की जाती है। रही बात शराबियों की तो ग्रामीण अंचलों में अत्यधिक शराब का सेवन कर नशे में धुत्त होकर फराटेबन दो पहिया वाहन के साइलेंसर में धुंआ फेकती सरपट गाड़ी दौड़ती कई बार नजर आती है। तो वहीं चार पहिया वाहन या अन्य वाहन भी शराब के नशे में धुत्त शराबी सरपट वाहन दौड़ाते नजर आते हैं। कई बार ऐसे में दुर्घटना के डर से लोग तेज गति में वाहन आने पर दूर भाग जाते हैं और वाहन चलाने वाले को गालियां देते नजर आते हैं। तो कई बार दुर्घटना भी हो जाती है।

मंगलवार को खवासा चौकी क्षेत्र के ग्राम वडलिपाडा का एक चार पहिया वाहन जीप क्रमांक एमपी 46 बी ए 4534 का चालक शराब के नशे में ऐसा धुत्त था कि, खवासा में सरपट वाहन दौड़ा कर लाया और बाजना मार्ग पर पहले साइड में खड़ी दो पहिया वाहन को चपेट में लिया जिसमें किरण चौहान की दो पहिया वाहन को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। वहीं थोड़ी ही आगे गणेश मंदिर के पास एक महिला आगे जा रही थी और पीछे शराब के नशे में धुत्त चालक इस वाहन को लेकर तेज गति से आ रहा था कि, नशेड़ी चालक के पास जीप में बैठे व्यक्ति ने हैंडब्रेक खींच लिया और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। ऐसे में ही महिला को पीछे से आ रही जीप का आभास हुआ और घबराई महिला एकदम एक दुकान की पेड़ी पर चली गई और अपनी जान बचाई।

उक्त दृश्य को देखकर हर कोई अचंभित हो गया और बड़ी दुर्घटना के आभास से ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। और माता रानी व भगवान गणेश का ही आभार माना कि, उनकी कृपा से ही बड़ी घटना होने से टल गई।

हैंडब्रेक के साथ जीप रुकते ही नशेड़ी चालक जीप से उतरा और नशे में धुत्त इतना था कि, सड़क नापते हुए बाजना रोड पर स्थित एक अवैध शराब के अड्डे की ओर चला गया।

जीप का वाहन मालिक यह कहते नजर आया कि, यह जीप मेरी है मैं वडलीपाड़ा रहता हूं, यह शराबी गांव बाहर खवासा में गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी दौड़ाने लगा, यह शराबी ड्राइवर हमारे गांव का ही है।

ट्रेन की चपेट में आया युवक,दोनों पैर कटे

माही की गूंज, बामनिया।

मंगलवार को दाहोद से रतलाम की ओर जा रही मेमू ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पैर कट गए।

मिली जानकारी के अनुसार, रतलाम निवासी असलम खान ट्रेन में चढ़ रहे थे इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वह प्लेटफार्म ओर पटरी के बीच जा गिरे जिससे उनके दोनों पैर कट गए। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए एम्बुलेंस की सहायता से पेटलावद स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को अन्यत्र रेफर कर दिया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422